सांध्य दैनिक

श्रीकंचनपथ

RNI. Reg. No. CHHHIN/2009/30534
डाक पंजीयन क्रं.-छ.ग./ दुर्ग /94/2023-25

लीपा पोती नहीं सिर्फ सच

वर्ष- 16 अंक - 296 | www.shreekanchanpath.com | संस्थापक एवं प्रेरणास्रोत- स्व. श्रीमती रजनी अग्रवाल | भिलाई, शुक्रवार 08 अगस्त 2025 | पृष्ठ 8- मूल्य 1/-

खास-खबर

एनआरडीए की जमीन खोदकर मुरूम चोरी, पुलिस की रेड- 7 जेसीबी-11 हाईवा जब्त

रायपुर। नवा रायपुर में अवैध मुरूम खनन का मामला सामने आया है। इस बात की जानकारी लगते ही गुरुवार (7 अगस्त) की रात दर्जन भर पुलिस कर्मियों ने सत्य साईं अस्पताल के पीछे स्थित जमीन में हो रहे अवैध खनन में रेड मारी। मामला मंदिर हसोद थाना क्षेत्र का है।

पुलिस का छापा पड़ते ही मुरूम लोड कर रहे जेसीबी और ट्रक के ड्राइवर भागने लगे। जिन्हें पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा है। मौके पर से कुल 7 जेसीबी और 11 हाईवा और एक ट्रैक्टर जब्त किया गया है। बताया जा रहा है ये जमीन एनआरडीए (नवा रायपुर विकास प्राधिकरण) का क्षेत्र है। जहां करोड़ों की जमीन को खोदकर मुरूम चोरी कर रहे थे।

जानकारी के मुताबिक, लगातार नवा रायपुर में अवैध मुरूम खनन की शिकायतें आ रही थी। जिसके बाद एएसपी विवेक शुक्ला के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम का गठन किया गया। 6 -7 अगस्त की दरमियानी रात को इस खनन की सूचना पुलिस को पहले ही मिल गई थी। पुलिस टीम के साथ एनआरडीए के डिप्टी कलेक्टर अरविंद शर्मा की भी टीम थी। टीम के वहां पर पहुंचने से अवैध खनन में लिप्त ड्राइवर और चालक सब गाड़ी छोड़कर भागने लगे, जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ा गया। हालांकि कागजी कार्रवाई के बाद इन्हें छोड़ दिया गया। इस एक्शन में मंदिर हसौद पुलिस की टीम भी शामिल थी। एएसपी विवेक शुक्ला ने कहा है कि एनआरडीए की तरफसे शिकायत मिलने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी।

दुर्ग की 48 अवैध कॉलोनियां 6 साल बाद अब होंगी नियमित

दुर्ग। 6 साल बाद निगम क्षेत्र की अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की तैयारी की जा रही है। इससे शहर की 48 कॉलोनियां नियमित हो जाएंगी। चरणबद्ध तरीके से शुरू होने जा रहे अभियान के पहले चरण में पायलेट प्रोजेक्ट में पांच कॉलोनियों को शामिल किया जाएगा। नियमितीकरण उन्हीं कॉलोनियों का किया जाएगा, जहां प्लाट एरिया का 10 प्रतिशत निर्माण हो चुका है। जिन प्लाट में निर्माण ही नहीं हुआ है उसे नियमित नहीं किया जाएगा। वर्ष 2019 में अवैध कॉलोनियों को नियमित किए जाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। निगम के भवन शाखा ने अवैध कॉलोनियों को ब्यौरा नगर तथा ग्राम निवेश विभाग को भेजा था। उस वक्त एक साथ सभी कॉलोनियों को नियमित करने की तैयारी थी, लेकिन अचानक प्रक्रिया पर ब्रेक लगा दिया गया। प्रक्रिया क्यों रोकी गई, नगर निवेश विभाग ने इसकी जानकारी भी निगम को नहीं दी। तब से अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण का मामला अटका था। महापौर अलका बाघमार की पहल पर निगम प्रशासन ने अब इन अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का निर्णय लिया है।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीण संपर्क मजबूत करने छत्तीसगढ़ को केंद्र से मिली 195 करोड़ की स्वीकृति

श्रीकंचनपथ न्यूज

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रधानमंत्री व केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय का जताया आभार

रायपुर। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दुर्गम और वनवासी अंचलों में ग्रामीण संपर्क और आधारभूत संरचना को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए भारत सरकार ने सड़क संपर्क परियोजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए छत्तीसगढ़ को 195 करोड़ की केंद्रीय सहायता राशि स्वीकृत की है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस महत्वपूर्ण स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह स्वीकृति छत्तीसगढ़ के उन सुदूर अंचलों में विकास का नया प्रकाश लेकर आएगी, जो दशकों से नक्सल हिंसा और भौगोलिक दुर्गमता से जूझते रहे हैं। यह राशि वहां के लोगों के लिए विकास, विश्वास और स्थायी शांति की सशक्त आधारशिला सिद्ध होगी। हमारी सरकार इस निधि का उपयोग पूर्ण पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ करेगी।

यह स्वीकृति वित्त मंत्रालय की जस्ट-इन-टाइम फंड रिलीज़ प्रणाली के अंतर्गत सिंगल नोडल एजेंसी स्पर्श मॉडल के माध्यम से दी गई है। मदर सैंक्शन सक्षम प्राधिकरण की अनुमति से तैयार किया गया है और यह PFMS (Public Financial Management System) पर अपलोड किया गया है। कुल 195 करोड़ में से 190.6125 करोड़ कार्यक्रम निधि और 4.3875 करोड़ प्रशासनिक निधि के रूप में स्वीकृत किए गए हैं, जो भारतीय रिज़र्व बैंक के माध्यम से राज्य को प्राप्त होंगे। स्पर्श दिशा-निर्देशों के अनुसार, किसी भी समय केवल एक सक्रिय मदर सैंक्शन मान्य रहेगा, और पूर्व शेष राशि को इसी में समाहित किया जाएगा।

नक्सल प्रभावित जिलों में संपर्क संरचना होगी मजबूत

यह निधि विशेष रूप से छत्तीसगढ़ के वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों—दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, कांकेर, बस्तर, राजनांदगांव, बलरामपुर, कोंडागांव और जशपुर—के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में नवीन ऑल-वेदर सड़कों, मौजूदा मार्गों के सुदृढ़ीकरण, सेतु निर्माण और क्रॉस-ड्रेनेज संरचनाओं के विकास के लिए दी गई है। इन संरचनाओं के माध्यम से बस्तियों को ब्लॉक व जिला मुख्यालयों, बाजारों, विद्यालयों और स्वास्थ्य केंद्रों से जोड़ा जाएगा, जिससे शासन की पहुंच और सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों में उल्लेखनीय सुधार होगा। विशेषकर बाढ़ग्रस्त और वर्षा ऋतु में अवरुद्ध हो जाने वाले क्षेत्रों में यह संपर्क संरचना जीवनरेखा का कार्य करेगी।

पूर्व स्वीकृत परियोजनाओं के अंतर्गत समायोजित

4.3875 करोड़ की प्रशासनिक निधि का उपयोग मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन, तकनीकी सहायता, क्षमता निर्माण, एवं एमआईएस प्लेटफॉर्म के माध्यम से डेटा प्रबंधन हेतु किया जाएगा। यह स्वीकृति पूर्व स्वीकृत परियोजनाओं के अंतर्गत समायोजित की गई है। बैच (2019-20) के तहत 56.82 करोड़, बैच (2022-23) के तहत 133.79 करोड़ समायोजित किए गए हैं। इस समायोजन के पश्चात बैच (2022-23) के लिए 217.39 करोड़ की राशि आगामी रिलीज़ हेतु शेष रहेगी। इस प्रक्रिया में पूर्व में जारी राशि और अर्जित ब्याज को सम्मिलित किया गया है। ई-बिल क्लियरेंस, मदर सैंक्शन और सिंगल नोडल एजेंसी स्पर्श प्रणाली के दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया गया है।

अस्पताल से निकलकर कोर्ट परिसर में शख्स ने लगा ली फांसी, पैर की चोट से था परेशान

■ तीन बेटियां व एक बेटा स्वीमिंग में हैं नेशनल चैंपियन

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। दुर्ग जिला न्यायालय परिसर में आज सुबह एक शख्स की फांसी के फंदे पर लटकती लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान दुर्ग नगर निगम के वार्ड 31 आपापुरा निवासी युवराज सार्वा (45) के रूप में हुई है। यह शख्स शुगर की बीमारी के चलते जिला अस्पताल में भर्ती था। शुक्रवार सुबह अस्पताल से निकलकर न्यायालय परिसर पहुंचा और फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मामले में दुर्ग सिटी कोतवाली पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है।

बताया जाता है कि युवराज सार्वा फ्लिहाल ई रिक्शा चलाकर अपने और परिवार का भरण पोषण कर रहा था। वह गंभीर रूप से शुगर की बीमारी से पीड़ित था। जिसके चलते उसके पैर में उभरा जख्म ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। इसी वजह से उसे दुर्ग जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शुगर की बीमारी के चलते पहले भी छह बार वह अस्पताल में भर्ती हो चुका था। सुबह 4 बजे के आसपास वह अस्पताल से निकलकर न्यायालय परिसर पहुंचा। यहां पर हनुमान मंदिर के पास टीन शेड में युवराज सार्वा ने नायलोन की रस्सी का फंदा लगाकर फांसी लगा लिया। इस बात की जानकारी नजदीक में रहने वाले राम अग्रवाल ने कोतवाली थाना पुलिस को दी।

राम अग्रवाल ने बताया कि रोज की तरह वे मार्निंग वॉक के लिए सुबह साढ़े 4 बजे निकले थे। घर से निकलकर न्यायालय परिसर से होकर वे मैदान की ओर जा रहे थे तो उनकी नजर टीन शेड के पास खड़े एक शख्स पर पड़ी। सामने पानी की बोतल होने से उन्हें लगा कि मार्निंग वॉक पर निकला कोई व्यक्ति वहां एक्सरसाइज कर रहा है। इसलिए वे अपने रास्ते चले गए। लेकिन पांच सवा पांच बजे जब वे लौट रहे थे तो व्यक्ति का सिर एक तरफझुका हुआ होने से उन्हें संदेह हुआ। नजदीक जाकर देखा तो वह फांसी के फंदे पर लटका हुआ था। बताते हैं कि मृतक की पांच में से तीन बेटियां और एक बेटा स्वीमिंग में नेशनल चैंपियन हैं। फ्लिहाल युवराज सार्वा के खुदकुशी का कारण जानने पुलिस जांच कर रही है।

बेटे ने लगाया प्रताड़ना का आरोप

मृतक युवराज सार्वा के एकलौते बेटे हेमंत सार्वा ने आरोप लगाया है कि उसके पिता हटरी बाजार में सब्जी बेचने का काम करते थे। लेकिन वहां के एक दुकानदार द्वारा सब्जी बेचने से मना कर दिया गया। जबकि उस जगह पर लगभग 50 साल पहले उसके दादा ने सब्जी बेचने का काम शुरू किया था। दुकानदार द्वारा सब्जी बेचने से मना करने पर वे मानसिक और आर्थिक रूप से टूट गए।

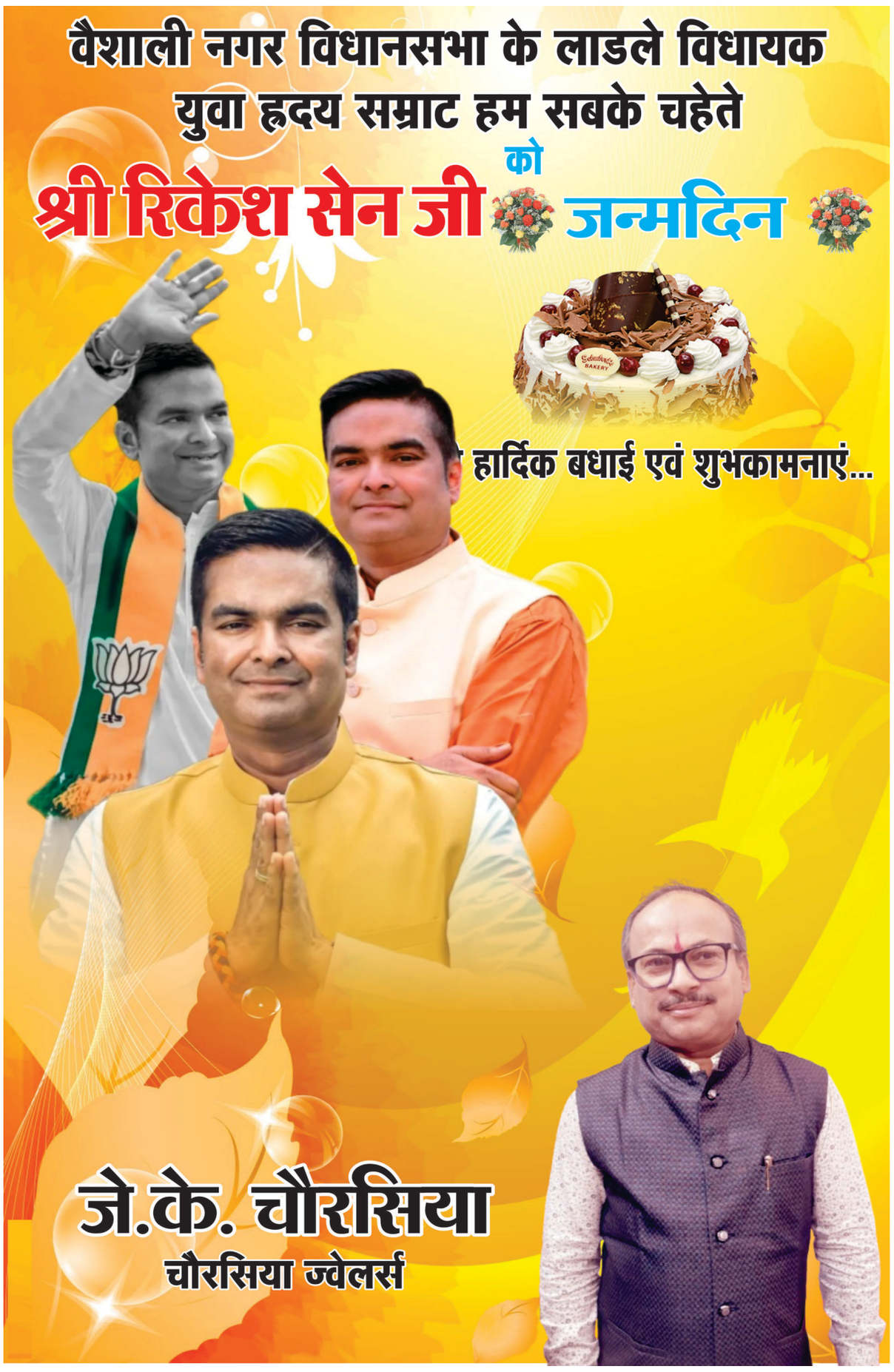

भारत अमेरिका के बीच आर्थिक संग्राम

श्रीकंचनपथ

गुस्ताखी माफ
- दीपक रंजन दास

भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक मोर्चे पर जंग छिड़ चुकी है। आज सात अगस्त से अमेरिका में भारतीय वस्तुएं महंगी होने वाली है। अमेरिका ने भारत से आयातित वस्तुओं पर 25 फीसद टैरिफलगा दिया है। 27 अगस्त से टैरिफ की यह दर 50 प्रतिशत हो सकती है। इसके चलते भारतीय निर्यातकों को परेशानी हो सकती है पर इसका सीधा खामियाजा अमेरिका में रह रहे लोगों को भुगतना पड़ेगा। वहां कीमतें बढ़ेंगी जिसके कारण उन्हें ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। दरअसल, अमेरिका भारत पर दबाव बनाना चाहता है। अमेरिका चाहता है कि वह भारतीय डेयरी एवं कृषि क्षेत्र में अपनी शर्तो पर प्रवेश करे। इसका सीधा सा मतलब यह है कि वह उत्पादों को यहां सस्ते में बेचकर स्थानीय डेयरी और कृषि उद्योग को तबाह कर दे। भारत इसके लिए तैयार नहीं है। भारत और अमेरिका के बीच टैरिफको लेकर बातचीत का दौर जारी है पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने साफकर दिया है कि भारत अपने कृषि और डेयरी उद्योग की हर कीमत पर रक्षा करेगा, फिर चाहे इसके लिए उसे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। प्रधानमंत्री ने कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामिनाथन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उनके शताब्दी समारोह में कहा कि भारत सुधारों के साथ आत्मनिर्भर हुआ है। भारत अपने कृषि और डेयरी क्षेत्र की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। राजनैतिक नेतृत्व को जो करना है, वह कर रहा है पर कुछ जिम्मेदारी हमारे यहां के नवधनाढ्य वर्ग की भी बनती है। जिस तरह ऑपरेशन सिन्दूर के बाद लोगों ने तुर्की और अजरबैजान के खिलाफमोर्चा खोला, यदि वह एक बार अमेरिका के खिलाफभी इसी तरह का मोर्चा खोल दे तो अमेरिका पर दबाव बन सकता है। पर यह उतना आसान भी नहीं होगा। भारत से विकसित देश अमेरिका को न केवल ब्रेन-ड्रेन होता है बल्कि यहां अमेरिकी उत्पादों के प्रति जबरदस्त आकर्षण भी है। उनका यह आकर्षण इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों से लेकर कारों तक साफदिखाई देता है। लोग अपनी साल भर की बचत को अमेरिका जाकर खर्च कर आते हैं। यदि अमेरिका भारत को डरा रहा है तो कुछ समय के लिए इन उत्पादों का बहिष्कार कर भारत उलटे अमेरिका पर भी दबाव बना सकता है। ऑपरेशन सिन्दूर के दौरान यदि तुर्की, अजरबैजान और चीन ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ दिया था तो बाद की परिस्थितियों में अमेरिका भी उसके साथ खड़ा नजर आया था। भारत चाहे न चाहे उसे अपनी असली ताकत को समझना होगा। भारत की विशाल आबादी और उसकी बढ़ती क्रय शक्ति लगभग सभी विकसित देशों की नजर में है। यह एक बहुत बड़ा बाजार है जो किसी भी विकसित देश के लिए नियमित आय का स्रोत बन सकता है। वक्त है कि भारत अपनी इस ताकत को पहचाने। सीधी लड़ाई में भारत को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है पर यदि यह लड़ाई भावनात्मक धरातल पर लड़ी जाए तो अमेरिका के बोल सुधर जाएंगे।

संपादकीय

जनता पर बुरा असर तो पड़ेगा ही

जनता से जुड़े मुद्दे पर सरकार या सरकारी संस्था कोई फैसला करती है तो बहुत सोचसमझ कर कोई फैसला करना चाहिए क्योंकि वादा करके वादा पूरा न करने वालों को जनता माफ नहीं करती है। खासकर ऐसे मुद्दे जिससे जनता को सीधा नगदी में फायदा होता है। उस फायदे को निरंतर जारी रखने की जगह सरकारी संस्था यदि उसे कम करती है तो भी जिन लाखों लोगों को नुकसान होगा वह सरकारी संस्था के इस काम को याद तो रखेंगे ही। इस संस्था ने उसे नुकसान पहुंचाया था अब सरकारी संस्था तो चुनाव नहीं लड़ती है, चुनाव तो सत्तारुढ़ दल को ही लड़ना है इससे जो राजनीतिक नुकसान होना है, वह तो सरकार का होना है, सत्तारुढ़ दल को होना है। भले ही वह तीन चार साल बाद हो।

“साय सरकार के रहते जनता उम्मीद नहीं कर रही थी कि भूपेश बघेल के समय शुरू की गई बिजली बिल हाफयोजना का दायरा 400 यूनिट से घटाकर 100 यूनिट कर दिया जाएगा। यह काम भले ही बिजली कंपनी ने किया है, लेकिन गुस्सा तो सरकार के खिलाफ ही फूटेगा।सरकार को यह बात मालूम है कि इस योजना को बंद करने का उसे नुकसान होगा इसलिए चुनाव के समय भाजपा ने इस योजना को लेकर कुछ नहीं कहा था लोगों को आश्वस्त किया था कि यह योजना बंद नहीं होगी। सरकार बनने के बाद भी कहा जाता रहा है कि बिजली हाफ योजना बंद नहीं होगी। अब इस योजना को बंद नहीं किया गया लेकिन ऐसा संशोधन किया गया है कि गरीब लोगों को तो कुछ लाभ मिले लेकिन जिन लोगों को हजार पांच सौ रुपए का फायदा हो रहा था, उनको फायदा बंद कर दिया गया है।”

सरकार चाहती तो पहले भी बंद कर सकती थी, अभी भी बंद कर सकती है लेकिन वह जानती है कि इस योजना को बंद करने से सरकार के खिलाफ नाराजगी बढ़ेगी। क्योंकि लाखों लोगों को जो फायदा हो रहा था, वह अब नहीं होगा। सरकार ने योजना को बंद नहीं किया है और यह बताने का प्रयास कर रही है कि योजना का दायरा 100 यूनिट करने पर भी लाखों लोगों को फायदा होगा। सरकार ने इसलिए भी योजना को पूरी तरह बंद नहीं किया है कि वह देखना चाहती है कि इस योजना में संशोधन का जनता पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर जनता में बहुत ज्यादा नाराजगी बढ़ती है तो हो सकता है सरकार कुछ दिनों बाद इस संशोधित योजना पर रोक लगा दे।

सरकार कहने को कह रही है कि वह हाफ बिजली से मुफ्त बिजली योजना की तरफ बढ़ रही है। यानी सरकार चाहती है कि लोग सूर्यघर सौर बिजली योजना का लाभ उठाए, मुफ्त बिजली पाएं। इसके लिए सरकार अनुदान भी दे रही है लेकिन सवाल उठता है कि किसी भी योजना का लाभ सारे लोग तो उठा नहीं पाते हैं जिनके यहां सौर प्लेट लगाने की जगह नहीं है, वह कैसे इस योजना का लाभ ले सकते हैं, खासकर शहरी क्षेत्र में। सौर प्लेट लगा भी ली तो उसका रखरखाव भी तो करना होगा। हो सकता है लोगों को रखरखाव करना न आए। कहने को मुफ्त बिजली योजना कहा जा रहा है, इसके फायदे भी हैं लेकिन जनता को दूर का फायदा की जगह वर्तमान में जो फायदा हो रहा था, वह बंद होने से सरकार के प्रति नाराजगी तो वर्तमान में बढ़ेगी है और इसका पूरा फायदा कांग्रेस उठाने का प्रयास करेगी।

कांग्रेस जनता को याद दिलाती रहेगी कि साय सरकार ने बिजली बिल हाफ योजना में कैसे धोखा दिया। कांग्रेस की सरकार थी को चार सौ यूनिट पर दो सौ यूनिट बिजली पर पैसा देना पड़ता था। साय सरकार के समय तो यह 100 यूनिट कर दिये जाने से जनता को पचास यूनिट का ही फायदा होगा। भाजपा सरकार ने वादाखिलाफी का कलंक पिछले चुनाव में धोया है, एक साल बाद भाजपा ने बिजली बिल हाफयोजना को लोगों को पूरा फायदा न देकर फिर वादा खिलाफी है। साय सरकार को इस योजना को शुरू में बंद कर देना था शुरू में बंद नहीं किया तो पूरे पांच साल इसका लाभ देना था। बीच में योजना का लाभ कम करने से जनता को लगेगा ही उसे हो रहे फायदे से वंचित किया गया है। उसे नुकसान पहुंचाया गया है।

वोट बैंक लालच ने बर्बाद किया हिमाचल-उत्तराखंड को

योगेंद्र योगी

विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार और डेवलपर्स पर्यावरणीय प्रभावों को नजरअंदाज कर रहे हैं। हिमाचल में 174 छोटे-बड़े हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स हैं, जो 11,209 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं। इन प्रोजेक्ट्स के लिए पहाड़ों को काटा जाता है।

लोकतंत्र में चुनी हुई सरकारों से यह अपेक्षा की जाती है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए दूरदृष्टि के साथ दूरगामी विकास को सिरे चढ़ाया जाए। इसके विपरीत नेताओं को सिर्फ वोट बैंक की चिंता है। इसके लिए तात्कालिक विकास की नीतियों के फायदे के लिए लोगों के जीवन से खिलवाड़ करने के साथ ही पर्यावरण के विनाशकारी प्रभावों की अनदेखी करना आम है। यही वजह है कि हिमाचल सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ी लताड़ लगाई है। कोर्ट ने कहा कि अगर अनियंत्रित विकास और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियां नहीं रोकी गईं, तो एक दिन पूरा हिमाचल नक्शे से गायब हो सकता है। यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब हिमाचल में बदलते पर्यावरण को लेकर चिंताएं बढ़ती जा रही हैं और विकास के नाम पर अंधाधुंध पेड़ काटे जा रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट की इस कड़ी टिप्पणी के अगले ही दिन उत्तराखंड के चमोली में चमोली जिले में हेलंग के समीप निर्माणाधीन एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट साइट के पास पहाड़ एक बार फिर से ढहकर धड़ाम से नीचे गिर गया। इस हादसे में कंपनी के 8 मजदूर घायल हो गए। साइट पर हादसे के वक्त करीब 300 मजदूर थे। जहां पर लैंडस्लाइड हुआ वहां पर 70 के करीब मजदूर कार्य कर रहे थे। ऐसे हादसों के बावजूद हिमालयी क्षेत्र के राज्यों की सरकारों ने कोई सबक नहीं सीखा है। इन राज्यों में विकास के नाम पर बर्बादी की कहानी लिखी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा कि कहा कि सरकारों का मकसद राजस्व बढ़ाना नहीं बल्कि पर्यावरण को बचाना होना चाहिए खासकर ऐसे संवेदनशील इलाकों में। कोर्ट ने यह टिप्पणी एक होटल कंपनी की याचिका खारिज करते हुए की। यह कंपनी जून 2025 की उस अधिसूचना के खिलाफ थी, जिसमें हिमाचल के श्री तारा माता हिल को ग्रीन एरिया घोषित कर नई प्राइवेट कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी गई थी। बेंच ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इस साल भी बाढ़ और भूस्खलन में सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों घर तबाह हो गए। यह साफ है कि प्रकृति इंसानी गतिविधियों से नाराज है। कोर्ट ने आगे कहा कि केवल प्रकृति को दोष देना गलत है। हिमाचल में पहाड़ों का खिसकना, सड़कों पर लैंडस्लाइड, मकानों का गिरना और सड़क धंसना, ये सब इंसानों की छेड़छाड़ का नतीजा है।

कोर्ट ने भाखड़ा और नाथपा झाकड़ी जैसे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिना सही भूगर्भ जांच और पर्यावरण अध्ययन के ये प्रोजेक्ट्स पहाड़ों को कमजोर कर रहे हैं। न्यूनतम जल प्रवाह का पालन न होने से नदियों में जलीय जीवन खत्म हो रहा है। आज सतलुज नदी एक नाले जैसी हो गई है। कोर्ट ने साफ किया कि अब समय रहते सख्त कदम न उठाए गए तो हिमाचल का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है। गौरतलब है कि पिछले एक सदी में हिमाचल प्रदेश में औसत तापमान 1.6 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। यह जलवायु परिवर्तन का एक स्पष्ट संकेत है, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश में आपदाओं की संख्या में तापमान में वृद्धि के कारण, बारिश की तीव्रता और आवृत्ति में वृद्धि हुई है, जिससे बाढ़ और भूस्खलन जैसी आपदाएँ आ रही हैं। हिमाचल के पांच जिले (चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी) भूकंप के लिए अति संवेदनशील क्षेत्र में आते हैं। भूकंप और लगातार बारिश से पहाड़ कमजोर हो जाते हैं, जिससे भूस्खलन की घटनाएं बढ़ती हैं। हिमाचल में लगभग 58.36 प्रतिशत भूमि तीव्र मिट्टी कटाव के खतरे में है। भारी बारिश के कारण मिट्टी बह जाती है, जिससे पहाड़ों की स्थिरता कम होती है और भूस्खलन का खतरा बढ़ता है। हिमाचल में ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। इससे नदियों में पानी का स्तर बढ़ जाता है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ता है। हिमाचल में अनियोजित-अवैज्ञानिक विकास कार्यों ने आपदाओं को और बढ़ावा दिया है।

विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार और डेवलपर्स पर्यावरणीय प्रभावों को नजरअंदाज कर रहे हैं। हिमाचल में 174 छोटे-बड़े हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स हैं, जो 11,209 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं। इन प्रोजेक्ट्स के लिए पहाड़ों को काटा जाता है। नदियों का प्रवाह बाधित होता है। वर्ष 2023 में कुल्लू और सैंज वैली में मलाना, सैंज और पार्वती प्रोजेक्ट्स के पास भारी नुकसान हुआ। मंडी, कुल्लू और शिमला में सड़क निर्माण के कारण बारिश में स्लिप और भूस्खलन की घटनाएं आम हैं। शिमला जैसे शहरों में बहुमंजिला इमारतें बन रही हैं, जो पर्यावरणीय चेतावनियों को नजरअंदाज करती हैं। हिमाचल में जंगलों को काटकर बिजली प्रोजेक्ट्स, सड़कों और पर्यटन के लिए जगह बनाई जा रही है।

वर्ष 1980 से 2014 तक किन्नौर में 90 प्रतिशत जंगल गैर-वन गतिविधियों के लिए हस्तांतरित किए गए, जिससे जैव विविधता और मिट्टी की स्थिरता को नुकसान हुआ। हिमाचल में हर साल लाखों पर्यटक आते हैं, खासकर कुल्लू, मनाली और शिमला जैसे क्षेत्रों में। इससे पर्यावरण पर दबाव बढ़ता है। होटल, रिसॉर्ट्स और अन्य निर्माण कार्यों के लिए पहाड़ों को काटा जाता है। कचरे का उचित प्रबंधन नहीं होता। इससे जल स्रोत और नदियां प्रदूषित होती हैं। बाढ़ जैसी स्थिति बनती है। पिछले कुछ सालों में हिमाचल में आपदाओं की संख्या और तीव्रता बढ़ी है। वर्ष 2021 में 476 लोगों की मृत्यु और करीब 1151 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। वर्ष 2022 में 276 लोगों की मृत्यु और 939 करोड़ रुपये का नुकसान, वर्ष 2023 में 404 लोगों की मृत्यु तथा 12000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

इसी तरह पिछले वर्ष 2024 में 358 लोगों की मृत्यु, 1004 घर क्षतिग्रस्त, और 7088 पशु हानि और 18 बादल फटने की घटनाओं ने 14 हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स को नुकसान पहुंचाया। कमोबेश ऐसे ही विनाशकारी हालात उत्तराखंड के हैं। इस साल भी बारिश के कारण उत्तराखंड में एक जून से लेकर अभी तक प्राकृतिक आपदाओं में 25 लोगों की मौत हुई है। उत्तराखंड में नदियां अक्सर भारी बारिश के कारण उफान पर आ जाती हैं, जिससे बाढ़ और भूस्खलन होता है। वर्ष 2013 की केदारनाथ आपदा में मंदाकिनी नदी में आई बाढ़ ने व्यापक विनाश किया था। वर्ष 2021 में उत्तराखंड में 17 प्रमुख बादल फटने की घटनाएं हुईं। जिससे 34 लोगों की मौत हो गई और 106 घर दब गए। आश्चर्य यह है कि इन दोनों राज्यों की सरकारों ने इन प्राकृतिक आपदाओं से कोई सबक नहीं सीखा। दोनों राज्यों में विकास के नाम अदूरदर्शी प्रतिकूल पर्यावरणीय गतिविधियां जारी हैं। इससे जाहिर है कि नेताओं की नजरें सिर्फ वोट बैंक तक सीमित रहती हैं, लोगों की जान-माल की यदि परवाह होती तो दोनों राज्यों के हालात इतने बदतर नहीं होते।

भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों में नया तनाव

विनीत नारायण

हाल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आयातित सामान पर 25 प्रतिशत टैरिफ और रूस से तेल और हथियारों की खरीद के लिए अतिरिक्त दंड की घोषणा की। यह कदम भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों में महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जा रहा है, विशेष रूप से तब जब दोनों देश एक व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। ट्रंप ने भारत और रूस को मृत अर्थव्यवस्था (डेड इकानमी) कह कर निशाना बनाया और भारत के उच्च टैरिफ और गैर-मौद्रिक व्यापार बाधाओं को इसका कारण बताया।

ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में वैश्विक व्यापार को प्रभावित करने वाली आक्रामक टैरिफ नीतियों को अपनाया है। 7 अगस्त, 2025 से लागू होने वाले 25 प्रतिशत टैरिफ का ऐलान करते हुए ट्रंप ने इसके लिए भारत के रूस से तेल और सैन्य उपकरणों की खरीद को प्रमुख कारण बताया। उनके अनुसार, भारत रूस का सबसे बड़ा ऊर्जा खरीदार है, जो यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियान के समय में अस्वीकार्य है। इसके अतिरिक्त, ट्रंप ने भारत के उच्च टैरिफ (जिसे उन्होंने दुनिया में सबसे अधिक बताया) और गैर-मौद्रिक व्यापार बाधाओं की भी आलोचना की। ट्रंप ने पहले 20-25 प्रतिशत टैरिफ की संभावना जताई थी, लेकिन अंतिम घोषणा में अतिरिक्त दंड भी शामिल किया गया। यह कदम भारत के फार्मास्यूटिकल्स, कपड़ा, र प्रतिशत और आभूषण और आटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है, जो अमेरिका के साथ भारत के व्यापार के महत्त्वपूर्ण हिस्सा हैं।

कांग्रेस नेता और लोक सभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ट्रंप के मृत अर्थव्यवस्था वाले बयान का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। कहा, हां, ट्रंप सही हैं। हर कोई जानता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मृत है, सिवाय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के। मुझे खुशी है कि ट्रंप ने यह तथ्य सामने रखा। दुनिया जानती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था खत्म हो चुकी है। भाजपा ने अडानी को मदद करने के लिए अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। राहुल ने मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाए, विशेष रूप से नोटबंदी और त्रुटिपूर्ण जीएसटी अर्थव्यवस्था के पतन के कारण बताए। उन्होंने यह भी पूछा कि ट्रंप के भारत-पाकिस्तान सीजफायर को लेकर बार-बार किए जा रहे दावों पर प्रधानमंत्री की चुप्पी क्यों है?

कांग्रेस पार्टी ने इस टैरिफ को भारत की विदेश नीति की विफलता के रूप में चित्रित किया। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, राहुल गांधी ने पहले ही इस बारे में चेतावनी दे दी थी। यह टैरिफ हमारी अर्थव्यवस्था, निर्यात, उत्पादन और रोजगार पर असर डालेगा। हम अमेरिका को फार्मास्यूटिकल्स निर्यात करते हैं, और 25 प्रतिशत टैरिफ से ये महंगे हो जाएंगे जिससे मांग कम होगी और उत्पादन तथा रोजगार पर असर पड़ेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाए और टैरिफ को भारत के व्यापार, एमएसएमई और किसानों के लिए हानिकारक बताया। अन्य विपक्षी नेताओं ने भी इस मुद्दे पर सरकार की आलोचना की। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने इसे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बुरे दिनों की शुरुआत बताया, जबकि असदुद्दीन ओवैसी ने ट्रंप को व्हाइट हाउस का जोकर कह कर उनकी आलोचना की।

वहीं, अर्थशास्त्रियों ने इस टैरिफ के भारत की अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभाव को लेकर मिश्रित राय व्यक्त की है। कुछ का मानना है कि इसका प्रभाव सीमित होगा जबकि अन्य ने दीर्घकालिक नुकसान की चेतावनी दी है। इंवेस्टमेंट इनफार्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आफ इंडिया (इक्रा) की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा, प्रस्तावित टैरिफ और दंड हमारी अपेक्षा से अधिक हैं, और इससे भारत की जीडीपी की वृद्धि पर असर पड़ सकता है। प्रभाव की गंभीरता दंड के आकार पर निर्भर करेगी। अर्नेस्ट एंड यंग इंडिया (ईवाई) के व्यापार नीति विशेषज्ञ अग्नेर सेन ने कहा, टैरिफ से समुद्री उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स, कपड़ा, चमड़ा और आटोमोबाइल जैसे क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित होंगे। ये क्षेत्र भारत-अमेरिका व्यापार में मजबूत हैं, और टैरिफ से इनकी प्रतिस्पर्धात्मकता कम हो सकती है। फाउंडेशन फार इकोनामिक डवलपमेंट के राहुल अहलूवालिया ने चेतावनी दी कि टैरिफ भारत को वियतनाम व चीन जैसी अन्य एशियाई अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कमजोर कर सकता है। उनके अनुसार, निर्यात आपूर्ति श्रृंखलाओं के भारत की ओर स्थानांतरण की संभावना नहीं है।

हालांकि, कुछ विशेषज्ञों ने आशावादी रुख भी अपनाया है। फिक्की के अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल ने कहा, हालांकि यह कदम दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारे निर्यात पर असर डालेगा। लेकिन हमें उम्मीद है कि यह अल्पकालिक घटना होगी और दोनों पक्ष जल्द ही एक स्थायी व्यापार समझौते पर पहुंच जाएंगे। भारत सरकार ने इस मुद्दे पर सतर्क और संयमित रुख अपनाया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में कहा, हम राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। भारत ने एक दशक में फ्रैजाइल फाइव से दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनने का सफर तय किया है। सरकारी सूत्रों ने संकेत दिया है कि भारत तत्काल जवाबी टैरिफ लगाने की बजाय बातचीत का रास्ता अपनाएगा। एक सूत्र ने कहा, चुप्पी सबसे अच्छा जवाब है। हम बातचीत की मेज पर इस मुद्दे को हल करेंगे।

कुल मिलाकर 25 प्रतिशत टैरिफ और अतिरिक्त दंड ने भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों में नया तनाव पैदा कर दिया है। राहुल गांधी और विपक्ष ने इसे सरकार की आर्थिक और विदेश नीति की विफलता के रूप में प्रस्तुत किया है, जबकि अर्थशास्त्रियों ने इसके मिश्रित प्रभावों की ओर इशारा किया है। जहां कुछ क्षेत्रों पर तत्काल असर पड़ सकता है, वहीं भारत के पास अन्य बाजारों में विविधता लाने और बातचीत के जरिए समाधान खोजने का भी अवसर है। यह स्थिति न केवल आर्थिक, बल्कि भू-राजनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्त्वपूर्ण है क्योंकि भारत को अपनी रणनीतिक स्वायत्तता और आर्थिक हितों को संतुलित करना होगा। देखना यह है कि आने वाले दिनों में सरकार इस समस्या से कैसे निपटती है।

(लेख में विचार निजी हैं)

रक्षाबंधन 9 अगस्त पर क्षमा करने और स्नेह बांटने का पर्व

राखी अर्थात रक्षाबंधन का पर्व भाई - बहन के बीच स्नेह के प्रतीक का सबसे बड़ा पर्व है। छोटे से लेकर दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर चुके भाई - बहनों को इस दिन का बेसब्री से इंतजार रहता है। यही वह पवित्र दिन है जब भाई - बहन अपने बीच पैदा हुए विवादों का पटाक्षेप कर रक्षाबंधन की डोरी को मजबूती दिया करते हैं। हिंदू धर्म में पौराणिक महत्व से परिपूर्ण रक्षाबंधन का पर्व सबसे बड़ा संदेश देने वाला पर्व कहा जा सकता है।

इस पर्व में एक बहन अपने भाई के ललाट पर मंगल तिलक लगाकर ईश्वर से उसके कुशल क्षेम की प्रार्थना करती है , तो भाई अपनी बहन के द्वारा दिए जाने वाले आशीर्वाद के लिए लालायित दिखाई पड़ते हैं । वर्तमान में कलयुगी स्वार्थ के चलते भाई-बहनों के बीच मनभेद का होना सामान्य रूप से दिखाई पड़ रहा है । खून के रिश्तों में इस तरह की विचार भिन्नता ने कुछ दूरियां बढ़ाते हुए प्रेम और स्नेह के बीच दरारें पैदा की हैं! रक्षाबंधन का पर्व ऐसी ही दूरियों को समाप्त करने का स्वर्णिम अवसर प्रदान करता है। किसी बात को लेकर एक-दूसरे के प्रति दुराव रखने वाले भाई-बहनों को संकल्पित होकर क्षमा जैसे गुण के वशीभूत उन काले बादलों से निकलने का प्रयास करना चाहिए, जिसने उनके प्रेम-स्नेह के ऊपर अपना आवरण ढंक दिया हो। यही इस पर्व का मुख्य मकसद है।

यदि बहन बड़ी हो तो भाई की त्रुटियों को नासमझी मानकर हवन कुंड में भस्म कर दे और यदि भाई बड़ा हो तो छोटी बहन की भूलों को आइने में जमीं धूल समझकर झाड़ डाले।

राखी महज एक धागा या सूत्र नहीं है , बल्कि यह एक बहन की भावनाओं, उसकी प्रार्थनाओं और भाई के प्रति अटूट विश्वास का प्रतीक है । यही वह स्नेह बंधन है जो भाई - बहन के बीच रिश्तों की मजबूती और स्थायित्व को प्रकट करता है ।

यही वह त्योहार है जो भाई - बहन के रिश्ते की खूबसूरती और उसकी महत्ता को उजागर करता है । एक ओर जहां बहन रक्षा का सूत्र बांधकर अपने भाई से जीवन भर की सुरक्षा का वचन मांगती है तो दूसरी ओर भाई भी अपने इस कर्तव्य को निभाने की प्रतिबद्धता का पालन करने का विश्वास दिलाता है । यह पर्व पारिवारिक सदस्यों को एक साथ आने का अवसर भी प्रदान करता है।

एक - दूसरे के प्रति कर्तव्यों के स्मरण बोध को भी रक्षा बंधन मजबूती प्रदान करता है। राखी का पर्व न केवल भाई - बहन के रिश्ते को बल प्रदान करता है वरन समाज में प्रेम एवं सदभाव को भी बढ़ाता है। वर्तमान की परिस्थितियों को देखकर बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि बदलती जीवनशैली ने हमें इतना ज्यादा व्यस्त कर दिया है कि इस दिन को

छोड़कर पूरे वर्ष भर हमारे पास इतना वक्त नहीं कि बहन कैसी है ? भाई क्या कर रहा है ? जानने का प्रयास कर सकें! ऐसे हालात कैसे बने ? इसका जिम्मेदार जैन है ? काफी सिर - फुटव्वल के बाद भी जवाब नकारात्मक ही है! कभी ऐसा लगता है कि यह सब समय का प्रभाव है! कभी लगता है सब अपने - अपने दायरों में कैद होकर रह गए हैं। आज की आराम - तलब जिंदगी और प्रतिदिन के संघर्षों ने रिश्तों को खोखला करने में कोई कसर नहीं छोड़ा है !

भागती-दौड़ती जिंदगी में पारिवारिक रिश्तों का स्वरूप तेजी के साथ बदलता जा रहा है । एक परिवार में रहने वाले भाई - बहनों के बीच तकरार और तनाव की लकीरें गाढ़ी होती जा रही हैं! एक - दूसरे की तकलीफों को समझने की जरूरत महसूस नहीं की जा रही है! भाई - बहन के रिश्ते आज की स्थिति में अपने प्रभुत्व और मान - सम्मान का प्रदर्शन करते ही दिखाई पड़ रहे हैं ! एक भाई को कब अपनी बहन की जरूरत है या एक बहन को कब भाई के सहारे की आवश्यकता है , इसे भी समझने में दोनों की हैसियत (स्टेटस) आड़े आ रही है ! ऐसी परिस्थिति में एक - दूसरे को संबल प्रदान करने की सोच ने तो लगभग दम ही तोड़ दिया है! सामाजिक व्यवस्था और पारिवारिक जरूरतों के चलते आज भाई - बहन लंबे समय तक साथ नहीं रह पाते हैं ! ऐसे में रक्षाबंधन का पर्व ही उन्हें फिर से निकट लाने में बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है । बावजूद इन सबके बढ़ती महंगाई , रिश्तों का खोखलापन और समय की कमी भाई को बहन के पास अथवा बहन को भाई के पास नहीं पहुंचने दे रहा है! यह कहने में कोई संकोच नहीं कि सभी रिश्तों की तरह भाई - बहन का रिश्ता भी अब पहले की तरह नहीं रहा ! सारे उलाहनों और मन - मुटावो को त्यागकर एक - दूसरे की भावनाओं को सम्मान देते हुए राखी की महत्ता को पहचानना ही आज के समय की सबसे बड़ी मांग है ।

श्रावण मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन मनाया जाने वाला रक्षाबंधन का पर्व स्नेह , कर्तव्य और विश्वास का प्रतीक है । राखी मात्र रंगीन धागा नहीं बल्कि संवेदनात्मक संकल्प है । यही वह सूत्र है जिसके द्वारा बहन , भाई के दीर्घायु की कामना करती है । इस पर्व की महत्ता इस लोक में ही नहीं देवलोक में भी होने का प्रमाण हमारे धर्म शास्त्रों में मिलता है । देवराज इंद्र से लेकर राजा बलि तक अनेक पौराणिक कथाएं राखी के मंगलसूत्र से भरी पड़ी हैं । इतना ही नहीं मुगलकालीन शासकों ने भी रक्षाबंधन के पर्व को सम्मान प्रदान करते हुए उसे अपनी कलाइयों में धारण किया । रक्षाबंधन भारतीय संस्कृति का एक ऐसा त्यौहार है जो यह बताता है कि रिश्तों की बुनियाद खून से ज्यादा भावनाओं और विश्वास पर टिकी होती है । यह पर्व जहां भाई - बहन के रिश्ते को मजबूती देता है , वहीं समाज में सुरक्षा, कर्तव्य और सामंजस्य की भावना को भी प्रगाढ़ करता है ।

रक्षाबंधन का पर्व वास्तव में देखा जाए तो एक पवित्र अनुष्ठान है , जो प्रत्येक भाई - बहन को कर्तव्यों का स्मरण कराता है । सार्वभौमिक भाईचारे का यह पर्व असीमित दृष्टिकोण एवं शांति की स्थापना करता है । यह एक ऐसा पर्व है जो जाति, पंथ, आयु, लिंग, धर्म, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, रंग और व्यक्तित्व के लक्षणों की सभी बाधाओं को तोड़ता है। रक्षा के पवित्र धागे राखी से बंधे होते हैं। इसमें शांति, प्रेम,पवित्रता, ज्ञान, दया के मूल स्वभाव का संकल्प समाया होता है। रक्षाबंधन पर्व के दिन भाई - बहन एक - दूसरे से दूर रहने की स्थिति में साथ बिताए पलों को याद कर भावुकता एवं बचपन की हंसी - ठिठोली , लड़ाई - झगड़े , प्यार - स्नेह और हर तरह की उछल - कूद वाली मस्ती भरी तस्वीरों में रंग भरने लगते हैं । यही इस पर्व का उल्लास कहा जा सकता है ।

ITR फाइल 500/-
Whatsapp पर बनवाऐं
Income Tax फाइल, GST रजिस्ट्रेशन, TDS रिफंड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट
CMA DATA, MSME, BALANCE SHEET, फूड लाइसेंस
हमारे Tax Expert आपकी मदद हेतु तैयार है।
www.onlytds.com
सम्पर्क - शेखर गुप्ता 9300755544 - 8878655544

श्रीकंचनपथ
भिलाई-दुर्ग

प्रिंट और डीजिटल मीडिया में
सभी प्रकार के विज्ञापन
के लिए
संपर्क करे
Mob.-:
9303289950
7987166110

खास खबर

वैशाली नगर विधानसभा में विकास कार्यों हेतु 44.99 लाख रूपए स्वीकृत

दुर्ग। कलेक्टर अभिजीत सिंह द्वारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजनांतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए वैशाली नगर विधानसभा के 03 निर्माण एवं सौंदर्यीकरण कार्यों के लिए 44 लाख 99 हजार 270 रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र विधायक श्री रिकेश सेन द्वारा अनुशंसित उक्त कार्यों का संपादन क्रियान्वयन एजेंसी आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा की जाएगी। जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार वार्ड क्रं 14 सड़क नं. जीरो शांतिनगर डोम के सामने सार्वजनिक मंच निर्माण कार्य के लिए 15 लाख रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी प्रकार वार्ड क्र. 24 के 32 एकड़ नाग मंदिर के पास सर्व सुविधायुक्त सार्वजनिक सामुदायिक भवने निर्माण हेतु 9 लाख 99 हजार 270 रूपए एवं वार्ड क्र. 04 नेहरू नगर स्थित भेलवा तालाब के सौंदर्यीकरण हेतु 20 लाख रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

वेद-गीता के बिना भारत की कल्पना असम्भवः डा. शर्मा

भिलाई। छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थान द्वारा 15 दिवसीय रोचक, ज्ञानवर्धक ,सरल और रोजगार परक संस्कृत शिक्षा समारोह का शुभारंभ विगत दिनों हुआ। आभासीय पटल (ऑनलाइन) संस्कृत भाषा के इस शिक्षण कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जुड़े संस्कृत व्याख्याताओं, शिक्षकों और विद्यार्थियों को लाभ मिला। इस गूगल मीट पर छत्तीसगढ़ के साथ उत्तराखण्ड, नई दिल्ली, चण्डीगढ़, वाराणसी, लखनऊ और उज्जैन आदि से भी संस्कृत अनुरागी जुड़े। भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय लखनऊ की कुलपति डॉ.मांडवी सिंह ने भरत मुनि के नाट्यशास्त्र पर व्यापक प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई विषय वस्तु नहीं जो नाटक में प्रस्तुत न की जा सके। भिलाई के आचार्य डॉ.महेश चन्द्र शर्मा ने रूपकों और अभिनय के विविध भेदों पर डाला और कहा कि यूनेस्को ने भी नाट्यशास्त्र को विश्व धरोहर माना है। इन्दिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ की डॉ.पूर्णिमा केलकर ने भी नाट्यशास्त्र पर प्रकाश डाला। इन्दिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के डॉ.राजन् यादव ने गोस्वामी तुलसीदास जयंती पर संस्कृत में उनके योगदान का उल्लेख किया। आचार्य डॉ.महेश शर्मा ने कि तुलसी मूलतः संस्कृत विद्वान् हैं। रामचरितमानस के मंगलाचरणों में उन्होंने बीस से अधिक सुन्दर संस्कृत पद्यों की रचना की है। डॉ.पूर्णिमा केलकर ने कहा कि राम साहित्य के सभी विद्वान संस्कृत में डूबे हुए हैं। अमृतसर से आये डॉ.रॉबिन शर्मा ने श्रीमद्भगवद्गीता प्रश्न मंच में विद्यार्थियों से रोचक 5-5 प्रश्न किये। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत शिक्षा संस्थान नई दिल्ली के डॉ.सौरभ दुबे ने संस्कृत को वैज्ञानिक भाषा बताते हुए विस्तार से अपनी बात रखी।

महापौर परिषद् की बैठकः अनेक कार्यों को मिली मंजूरी

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई के महापौर परिषद की बैठक महापौर नीरज पाल की अध्यक्षता एवं आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय की उपस्थिति में आहूत की गई। बैठक में नगर निगम की महती योजना गोकुल नगर में निकलने वाले गोबर से बायो गैस प्लांट स्थापित किए जाने सहित परिषद ने अन्य प्रस्ताओं को स्वीकृति प्रदान की है।

महापौर परिषद के सदस्यों के समक्ष 19 एजेण्डा विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। जिसमें प्रमुख रूप से बायो गैस प्लांट की स्थापना, हाइड्रोलिक एलिवेटर का किराया दर निर्धारण, निजी भवन/भूमियो के शुल्क में वृद्वि, वाटर एटीएम, सक्शन कम जेटिंग मशीन का किराया निर्धारण, जवाहर मार्केट का उन्नयन एवं विकास, जलकर, अभिमत प्रदाय, श्रमिक प्रदाय, पाइप लाईन एवं 15वें वित्त आयोग अंतर्गत प्रस्ताव शामिल है।

भिलाई निगम अंतर्गत गोकुल नगर में बायो गैस प्लांट की स्थापना, हाइड्रोलिक एलिवेटर का किराया दर निर्धारण एवं निजी भवनों/भूमियों के स्वत्वाधिकार के अंतरण के शुल्क में वृद्वि हेतु महापौर परिषद के सदस्यों से अपनी सहमति प्रदान की। वार्ड क्रं. 59 सेक्टर 05 सड़क 03 स्थित वाटर एटीएम की स्थानांतरण, सक्शन कम जेटिंग मशीन 9000 लीटर का किराया निर्धारण एवं जवाहर मार्केट का उन्नयन एवं विकास कार्य को मंजूरी दी गई। जलकर विषयक संशोधन, अभिमत/आपत्ति/अनापत्ति प्रदान करने जॉच प्रतिवेदन, निगम के जलकार्य विभाग में कुशल, अर्धकुशल एवं अकुशल श्रमिक उपलब्ध कराने एवं 2.72 एमएलडी जलशोधन संयंत्र से क्लीयर वाटर प्रदाय हेतु संपवेल, पम्प हाउस एवं राइजिंग मेन पाइप लाइन बिछाने के कार्य को महापौर परिषद के सदस्यों द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। 15वें वित्त आयोग ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के एसडीपी से मिलान कर शासन को प्रस्ताव प्रेषित करने एवं अन्य 3 एजेण्डा पर सदस्यों की सहमति मिली।

बैठक में महापौर परिषद के सदस्य सीजू एन्थोनी, लक्ष्मीपति राजू, संदीप निरंकारी, लालचंद वर्मा, साकेत चंद्राकर, एकांश बंछोर, केशव चैबे, चंद्रशेखर गंवई, रिता सिंह गेरा, नेहा साहू, उपायुक्त/सह सचिव नरेन्द्र बंजारे, जोन आयुक्त येशा लहरे, अमरनाथ दुबे, कार्यपालन अभियंता रवि सिन्हा, अनिल सिंह, वेशराम सिन्हा, अरविंद शर्मा, विनीता वर्मा, राजस्व अधिकारी जे.पी. तिवारी, लेखाधिकारी चंद्रभूषण साहू, स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली, सहायक अभियंता दीपक देवांगन, उप अभियंता अर्पित बंजारे, देवव्रत राजपूत सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

भिलाई के पत्रकार कमल शर्मा को इंटीग्रेटेड ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने प्रदान की डॉक्टरेट की मानद उपाधि

श्रीकंचनपथ न्यूज

नई दिल्ली/भिलाई। इंटीग्रेटेड ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने गुरुवार को गुड़गांव के होटल हॉलिडे इन में आयोजित एक भव्य समारोह में भिलाई के पत्रकार डॉ कमल किशोर शर्मा को मानद डॉक्टरेट (Honoris Causa) की उपाधि से सम्मानित किया। यह सम्मान उनके समाज के प्रति असाधारण योगदान और प्रतिबद्धता के लिए प्रदान किया गया।

समारोह में यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधियों ने डॉ. कमल शर्मा की सामाजिक सेवा, नेतृत्व और समाज के उत्थान में उनके उल्लेखनीय कार्यों की सराहना की। इंटीग्रेटेड ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जो अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त संस्था है और अमेरिकन लाइब्रेरी, यूएसए का संस्थागत सदस्य है, ने इस उपाधि को रजिस्ट्रेशन नंबर IN-DL738958175143 95 के तहत प्रदान किया।

इंटीग्रेटेड ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जो एक ISO 9001:2018 प्रमाणित संस्थान है और GNCT दिल्ली के तहत ट्रस्ट एक्ट 1961 के अंतर्गत पंजीकृत है। इंटीग्रेटेड ग्लोबल यूनिवर्सिटी के कॉरपोरेट कार्यालय, जो चांदनी चौक, दिल्ली-110006 में स्थित है, ने इस अवसर पर एक बयान जारी कर कहा, डॉ. कमल किशोर शर्मा ने अपने कार्यों से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। उनकी उपलब्धियां और समर्पण न केवल प्रेरणादायक हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल हैं। इस समारोह में संस्था के डायरेक्टर तपन काकोटी सहित विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों, शिक्षाविदों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

डॉ. कमल शर्मा ने इस सम्मान के लिए यूनिवर्सिटी के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा, यह मेरे लिए गर्व का क्षण है। मैं अपने कार्यों को और अधिक उत्साह के साथ समाज के कल्याण के लिए समर्पित करता रहूंगा। इंटीग्रेटेड ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने अपने मिशन के तहत उन व्यक्तियों को मानद उपाधियाँ प्रदान करने का कार्य जारी रखा है, जो समाज में उत्कृष्ट योगदान देते हैं।

आयुक्त ने प्रगति मार्केट में निर्मित दुकानों के संचालन प्रक्रिया में लाई तेजी

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई जोन-04 अंतर्गत प्रगति मार्केट के संचालन, प्रस्तावित नाली, एस.एल.आर.एम. सेंटर, सीमेंटीकरण रोड एवं साफ-सफाई व्यवस्था का निरीक्षण आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय द्वारा किया गया।

आयुक्त ने जोन आयुक्त अमरनाथ दुबे के साथ जोन क्रमांक 04 खुर्सीपार अंतर्गत प्रगति मार्केट का निरीक्षण कर निर्मित दुकानों के संचालन हेतु रूचि की अभिव्यक्ति ऑफर की प्रक्रिया अविलंब करने निर्देशित किये है। दुकानों का नियमानुसार किराया निर्धारण हेतु महापौर परिषद के बैठक में रखा जाएगा । वार्ड क्रं. 38 सोनिया गांधी नगर में अधोसंरचना मद से प्रस्तावित नाली निर्माण कार्य का अवलोकन किया गया। शासन को प्रस्ताव भेजा गया है, स्वीकृति पश्चात कार्य कराया जाएगा। वार्ड क्रं. 42 गौतम नगर में एस.एल.आर.एम. सेंटर का विस्तार हेतु निर्माण किया जा रहा है। जहां घरो एवं दुकानों से निकलने वाले कचरे को एकत्रित कर पृथक्करण किया जाएगा। एकत्रित कचरे को छाटकर खाद निर्माण एवं अन्य आवश्यक सामग्रियों को पुनः निर्माण हेतु भेजा जाएगा। निरीक्षण कर पर्याप्त पानी सिंचाई करने निर्देशित किया गया। साथ ही वार्ड में चल रहे साफ-सफाई व्यवस्था का जायजा लिए कार्यरत कर्मचारियों को सफाई में समस्या आने पर जोन आयुक्त को सूचित करने निर्देशित किया गया।

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से बिजली बिल हुआ जीरो, चेहरे पर आई राहत की मुस्कान

श्रीकंचनपथ न्यूज

दुर्ग। दुर्ग जिले के ग्राम मोहलई में रहने वाले देवांगन परिवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर पैनल लगवाकर ना केवल मुफ्त बिजली का लाभ उठा रहे हैं, बल्कि बिजली के बिलों से भी राहत पा रहे हैं। जहां पहले हर महीने भारी भरकम बिजली बिल उन्हें चिंता में डाल देता था, वहीं अब उनके चेहरे पर राहत की मुस्कान है। अनिता देवांगन के पति आधुनिक तकनीकों में भी रुचि रखते हैं।

श्रीमती देवांगन ने बताया कि उन्होंने अपने घर की छत पर 6 किलोवॉट का सोलर पैनल लगवाया है, जिसकी कुल लागत करीब 3 लाख रुपये आई। इस योजना के तहत उन्हें केंद्र सरकार से 75 हजार रूपए की सब्सिडी भी मिली, जिससे लागत और भी कम हो गई। पहले गर्मियों में बिजली का बिल 4 से 5 हजार रुपए तक आता था। बाकी सीजन में 2500 रुपए तक बिल देना पड़ता था। लेकिन अब पिछले छह महीनों से बिजली बिल जीरो आ रहा है। उनके घर में 4 एसी, 3 टीवी और अन्य बिजली उपकरण चलते हैं, फिर भी सोलर एनर्जी के कारण उन्हें बिजली बिल की कोई फिक्र नहीं है। श्रीमती देवांगन के पति श्री हरिहर प्रसाद देवांगन नवापारा में ऑटो पार्ट्स की दुकान चलाते हैं। इस पहल से देवांगन परिवार को बड़ी राहत मिली है। इनकी घर की आवश्यकता अभी केवल दो केवी है, शेष केवी को सरकार को बेच पैसा कमाने की योजना है। अब जो पैसे पहले बिजली बिल में जाते थे, उन्हें वे बच्चों की पढ़ाई और घर के अन्य जरूरी कामों में लगा पा रहे हैं।

हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता - स्वतंत्रता का उत्सव, स्वच्छता के संग थीम पर 15 अगस्त तक स्वतंत्रता सप्ताह का आयोजन

कार्यक्रम अंतर्गत गतिविधियों के संचालन करने हेतु क्षेत्रवार नोडल अधिकारी नियुक्त

श्रीकंचनपथ न्यूज

दुर्ग। 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 02 अगस्त से 15 अगस्त, 2025 तक तीन चरणों में (प्रथम चरण 02 से 08 अगस्त, द्वितीय चरण 09 से 12 अगस्त, तृतीय चरण 13 से 15 अगस्त 2025) किया जा रहा है, जो ''हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता - स्वतंत्रता का उत्सव, स्वच्छता के संग'' थीम पर आधारित है।

इसके अंतर्गत सभी भारतीय नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज अपने घर पर फहराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, ताकि आमजन में देश भक्ति की भावना विकसित हो तथा राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान में वृद्धि हो। कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने उक्त कार्यक्रम अंतर्गत गतिविधियों के संचालन करने हेतु क्षेत्रवार नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पंचायत क्षेत्रों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दुर्ग को, नगर पालिका निगम क्षेत्र में आयुक्त नगर पालिक निगम (सर्व) जिला दुर्ग को, नगर पालिका परिषद् क्षेत्रों में मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद् (सर्व) जिला दुर्ग को तथा नगर पंचायत क्षेत्रों में मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत (सर्व) जिला दुर्ग को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। सभी कार्यालयों/विभागीय गतिविधियों के संचालन हेतु संबंधित कार्यालय प्रमुख (सर्व) जिला दुर्ग प्रभारी अधिकारी होंगे। सभी नियुक्त नोडल अधिकारियों को संस्कृति विभाग द्वारा दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करने कहा गया है।

कार्यक्रम अंतर्गत जारी दिशा-निर्देश के अनुसार जिले के अन्तर्गत सार्वजनिक उपक्रमों स्व-सहायता समूहों, सामाजिक संगठनों आदि के समस्त कर्मचारियों एवं उनके परिवार की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। कार्पोरेट और निजी संगठनों को भी सीएसआर संसाधनों सहित भाग लेने और योगदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्य सरकार की वेबसाइट्स और सोशल मीडिया का उपयोग कर जागरूकता का निर्माण करने तथा ''हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता-स्वतंत्रता का उत्सव, स्वच्छता के संग'' आयोजित कार्यक्रम को वेबसाइट के माध्यम से लिंक किया जाएगा। शासन स्तर पर मॉनिटरिंग कर ग्राम सरपंचों एवं नगरीय निकाय के अन्य सदस्य एवं पदाधिकारियों की सहभागिता सुनिश्चित कर तिरंगा कोड को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त तिरंगा की मांग अनुसार व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। शासकीय स्तर पर प्रत्येक गाँव में तिरंगा वितरण और बिक्री केन्द्र स्थापित किया जाना है। इसके लिए स्थानीय स्व-सहायता समूहों को तिरंगा के निर्माण एवं ग्राम पंचायतों द्वारा बड़े पैमाने पर समूह में खरीदी के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्य के सभी जिलों में तिरंगा के वितरण/बिक्री केन्द्र के रूप में पोस्ट ऑफिस/उचित मूल्य की दुकान का नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। टोल नाका, चेक पोस्ट आदि में पैम्पलेट-स्टीकर वितरण किये जाएंगे।

विश्व स्तनपान सप्ताह 2025 का सफल आयोजन

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। सेल- भिलाई इस्पात संयंत्र के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र, भिलाई के शिशु रोग विभाग द्वारा 1 से 7 अगस्त 2025 तक विष्व स्तनपान सप्ताह का आयोजन 'स्तनपान को प्राथमिकता दें -टिकाऊ समर्थन प्रणाली बनाएं' थीम के साथ किया गया। विश्व स्तनपान सप्ताह एक वैष्विक पहल है, जिसका उद्देश्य स्तनपान के प्रति जागरूकता बढ़ाना, इससे जुड़ी भ्रांतियों को दूर करना तथा माताओं को आत्मविष्वासपूर्वक स्तनपान कराने हेतु सहयोगी वातावरण प्रदान करना है।

इस सप्ताह का उद्घाटन समारोह दीप प्रज्वलन और पोस्टर प्रदर्शनी के उद्घाटन के साथ हुआ, जिसमें कार्यपालक निदेशक (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं) डॉ. एम. रवींद्रनाथ द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया तथा सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। इसके पश्चात शिशु रोग विभाग के निवासियों द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक नाट्य प्रस्तुति एवं स्तनपान नीति से लाभान्वित माता-पिता द्वारा अनुभव साझा किए गए।

राजहरा माइंस अस्पताल में भी इसी दिवस से विष्व स्तनपान सप्ताह का आरंभ किया गया, जहाँ उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. कौशिक किशोर द्वारा एक जन-जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सप्ताह भर शिशु एवं नवजात इकाई, प्रसूति वार्ड तथा बाल रोग ओपीडी में जागरूकता सत्र आयोजित किए गए। इसके अतिरिक्त, 6 अगस्त को बीएसपी के निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) विभाग के सहयोग से मिशन लक्ष्मी परियोजना के अंतर्गत दुर्ग स्थित शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एक सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्राओं को अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं विभागाध्यक्ष (शिशु रोग) डॉ. संबिता पांडा एवं वरिष्ठ सलाहकार डॉ. शुभस्मिता पटनायक द्वारा स्तनपान से संबंधित मिथकों के खंडन एवं उसे निरंतर जारी रखने के सतत उपायों पर व्याख्यान दिया गया।

सप्ताहभर की सभी गतिविधियाँ अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं विभागाध्यक्ष डॉ. संबिता पांडा के नेतृत्व में तथा कार्यपालक निदेशक (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं) डॉ. एम. रवींद्रनाथ, मुख्य चिकित्सा अधिकारीगण डॉ. विनीता द्विवेदी, डॉ. कौशलेंद्र ठाकुर, डॉ. सौरभ मुखर्जी एवं डॉ. उदय कुमार के मार्गदर्शन एवं समर्थन से सम्पन्न हुईं।

साथ ही इस आयोजन में नवजात शिशु इकाई प्रभारी डॉ. सुबोध साहा, विभाग के सलाहकारगण डॉ. मीता सचदेव, डॉ. नूतन कुमार वर्मा, डॉ. कौशिक किशोर, डॉ. माला चैधरी, डॉ. शुभस्मिता पटनायक, डॉ. रुचिका ताम्रकार एवं डॉ. आनंद मोहन विश्वकर्मा का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस सप्ताह का समापन संविदा नर्सिंग स्टाफ के लिए आयोजित लैक्टेशन मैनेजमेंट विषयक शैक्षिक सेमिनार के साथ हुआ, जिसे वरिष्ठ सलाहकार डॉ. माला चैधरी के निर्देशन में तथा विभाग के रेसिडेंट डॉक्टरों द्वारा संचालित किया गया।

Since 1972
CROWN® - TV
Choice Of Millions
LED Available 16 -20 -22 - 24 - 32-40-50-55-65

Maa Durga Electronics
9827183839
Rohit Electronics
94242-02866
Premier sales: 8959493000
A Leela Electronics: 9425507772
Reena Electronics: 9329132299
Shree Electronics: 7000827361
Authorised Distributers For Chhattisgarh
Trade Enquiry: 98262-52372

खास खबर...

सरोना को मिली 100 बिस्तरों वाले अस्पताल की सौगात

रायपुर। रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सरोना को जल्द ही एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सरोना में 100 बिस्तरों की क्षमता वाले एक आधुनिक अस्पताल के निर्माण को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। यह अस्पताल अठारह करोड़ छब्बीस हजार रुपये की लागत से बनाया जाएगा। इस परियोजना के पूरा होने के बाद सरोना और इसके आसपास के हजारों नागरिकों को प्राथमिक से लेकर आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेंगी, जिससे उन्हें बड़े शहरों के अस्पतालों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

उल्लेखनीय है कि इसके लिए पद संरचना की स्वीकृति पूर्व से ही राज्य शासन दे चुका है अर्थात यह पहली बार है कि भवन निर्माण कार्य प्रारंभ होने से पहले ही पद निर्माण की स्वीकृति मिल गई है। यह अस्पताल पूरी तरह से आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं से युक्त होगा। इसमें सामान्य चिकित्सा, प्रसूति एवं शिशु रोग, सर्जरी, आपातकालीन सेवाएं, एक्स-रे, पैथोलॉजी, ओपीडी, इनडोर मरीजों के लिए बिस्तर सुविधा, दवाइयों की उपलब्धता जैसी सभी मूलभूत सेवाएं सुनिश्चित की जाएंगी। इससे न केवल स्वास्थ्य के क्षेत्र में आमजन को राहत मिलेगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।

रायपुर पश्चिम में पहली बार 100 बिस्तर अस्पताल खुलने जा रहा है।इस महत्वपूर्ण स्वीकृति पर रायपुर पश्चिम के विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री राजेश मूणत ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी के प्रति हृदय से आभार प्रकट किया है।

श्री मूणत ने कहा कि यह अस्पताल न केवल सरोना बल्कि पूरे रायपुर पश्चिम क्षेत्र के लिए वरदान साबित होगा। अब लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं अपने ही क्षेत्र में उपलब्ध होंगी और इलाज के लिए दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि यह जनहित में लिया गया एक दूरदर्शी निर्णय है, जो प्रदेश सरकार की संवेदनशीलता और विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

राजेश मूणत ने आगे कहा कि रायपुर पश्चिम क्षेत्र की जनता की सेवा के लिए वे निरंतर प्रयासरत हैं। इस अस्पताल के निर्माण के साथ ही आने वाले दिनों में क्षेत्र के अन्य इलाकों में भी कई महत्वपूर्ण विकास कार्य आरंभ किए जाएंगे। इनमें 1000 सीटर नालंदा लाइब्रेरी 19 करोड़ रुपयों की लागत से पानी टंकी तकरीबन 18=19 करोड़ रुपयों की लागत से वर्किंग वुमन हॉस्टल सड़कों का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण, जल निकासी व्यवस्था का सुधार, स्कूलों और शिक्षा संस्थानों का उन्नयन, पेयजल आपूर्ति को सुदृढ़ बनाना और सामुदायिक भवनों का निर्माण जैसी योजनाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हर वर्ग, हर समुदाय के विकास के लिए सरकार की योजनाएं धरातल पर तेजी से उतारी जा रही हैं और इसका लाभ सीधे आम जनता तक पहुंच रहा है।

अतिशीघ्र बंगाली होटल हीरापुर के पास एवं कबीर चौक के पास करीब करीब 50 करोड़ रुपयों की लागत से ओवर ब्रिज का निर्माण भी प्रारंभ होगा। यही नहीं साइंस कॉलेज में अत्याधुनिक छात्रावास तथा आमानाका में बहुउद्देशीय खेल परिसर निर्माण का भी प्रस्ताव है। इस स्वीकृति की जानकारी सामने आने के बाद सरोना और आसपास के क्षेत्रों में हर्ष का माहौल है। स्थानीय नागरिकों ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि यह बहुत लंबे समय से प्रतीक्षित मांग थी, जो अब पूरी हो रही है। क्षेत्रवासियों ने मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया है और विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेश मूणत की सक्रियता और प्रतिबद्धता की सराहना की है। यह अस्पताल रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। छत्तीसगढ़ सरकार की यह पहल न केवल जनहित में एक सार्थक कदम है, बल्कि यह प्रदेश में स्वास्थ्य ढांचे को सशक्त करने की दिशा में एक प्रभावशाली प्रयास भी है।

महिलाओं के लिए बड़ी पहलः रायपुर में बनेगा पहला 'महिला शांति गृह', मिलेगा तत्काल सहारा

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। नगर निगम रायपुर में महापौर परिषद एमआईसी की बैठक महापौर मीनल चौबे की अध्यक्षता, आयुक्त विश्वदीप, एमआईसी सदस्य मनोज वर्मा, दीपक जायसवाल, गायत्री सुनील चंद्राकर, सरिता आकाश दुबे, संतोषी सीमा साहू, अवतार भारती बागल, भोला राम साहू, सुमन अशोक पाण्डेय, डॉ. अनामिका सिंह, महेन्द्र खोडियार, अमर गिदवानी, नंदकिशोर साहू, खेम कुमार सेन,संजना हियाल सहित अपर आयुक्तगणों, अधीक्षण अभियंतागणों, उपायुक्तों, जोन कमिश्नरों, पालन अभियंताओं, विभागो के प्रभारी अधिकारियों की उपस्थिति में हुई। एमआईसी की बैठक में महापौर की अध्यक्षता में 42 एजेण्डो पर विचार कर एजेण्डावार आवश्यक निर्देश दिये गये।

महापौर मीनल चौबे के नेतृत्व में रायपुर नगर निगम की एमआईसी ने पहली बार मध्यम वर्गीय परिवारों की महिलाओं के कल्याणार्थ रायपुर में नरैया तालाब के पास महिला शांति गृह का निर्माण करने का आवश्यक प्रस्ताव बनवाया है। एमआईसी ने बैठक में रायपुर में नरैया तालाब के समीप रिक्त भूमि पर महिला शांति गृह का निर्माण करने के प्रस्ताव को नियमानुसार स्वीकृति प्रदान कर दी है। योजना का उद्देश्य महिलाओ को अस्थायी आश्रय देना, परामर्श सेवाएं प्रदान करना होगा। यह महिला शांति गृह मध्यम वर्गीय परिवारों की उन महिलाओं के लिए उपयोगी होगा, जो घरेलू हिंसा, दहेज प्रताडना या किसी भी प्रकार की समस्या में है और जिन्हे तत्काल सहायता की आवश्यकता है। यह परियोजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इस हेतु 4 करोड़ 99 लाख 25 हजार का प्राक्कलन तैयार किया गया है। महिला शांति गृह के संचालन एवं संधारण हेतु 4 दुकानों का निर्माण प्रस्तावित किया गया है। प्रस्ताव की प्रशासकीय स्वीकृति सहित निविदा आमंत्रण की अनुमति एमआईसी ने महापौर मीनल चौबे की अध्यक्षता में महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से सर्वसम्मति से प्रदान की है।

एमआईसी ने निगम सभापति सूर्यकांत राठौड़, के पत्र पर विचार कर महापौर मीनल चौबे की अध्यक्षता में नगर निगम रायपुर द्वारा पूर्व वर्षों में गणेश उत्सव के अवसर पर झांकियों और स्थलों की सुन्दरता, स्वच्छता, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों पर दिये जाने वाले पुरस्कार की परंपरा पुन: प्रारंभ करने एवं वर्ष 2025 गणेश उत्सव से पुरस्कार योजना प्रारंभ करने का निर्णय नगर की सांस्कृतिक गरिमा में वृद्धि सहित स्वच्छता व सार्वजनिक सजावट के उद्देश्य को बल प्रदान करने सर्वसम्मति से लिया गया। एमआईसी ने नगर निगम रायपुर के जयस्तंभ चौक के समीप पुराने निगम कार्यालय की 22377 वर्गमीटर क्षेत्रफल की भूमि का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने एवं रायपुर निगम को राजस्व प्राप्ति हेतु रेवेन्यु शेयरिंग मॉडल पर कमर्शियल काम्पलेक्स कम पार्किंग निर्माण हेतु आरएफपी तैयार करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया है।

एमआईसी ने शहरी गरीबी उपशमन एवं समाज कल्याण कल्याण विभाग के प्रस्ताव अनुसार निराश्रित पेंशन योजना के 428 पात्र नवीन प्रकरणों और राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के 88 पात्र नवीन प्रकरणों को सर्व सम्मति से पारित किया है। सामान्य प्रशासन विभाग के प्रस्ताव अनुसार सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक दयानंद सेन, प्रभारी जोन स्वास्थ्य अधिकारी संजीव शर्मा, अधीक्षण अभियंता संतोष कुमार पाण्डेय को सेवानिवृत्ति उपरांत 1 वर्ष की संविदा नियुक्ति देने की अनुशंसा कर नियमानुसार विचारार्थ प्रस्ताव राज्य शासन को भेजने निर्णय लिया है। नवीन सरस्वती नगर निगम उ.मा. शाला पुरानी बस्ती उच्च श्रेणी शिक्षक प्रेमलता यादव को 28 फरवरी 2025 को सेवानिवृत्ति पश्चात सत्रांत 30 अप्रैल 2026 तक पुनर्नियुक्ति देने और माधव राव सप्रे उत्कृष्ट हिन्दी माध्यम विद्यालय बूढ़ापारा के व्याख्याता के. राजगोपाल को 31 जुलाई 2025 को सेवानिवृत्ति पश्चात सत्रांत 30 अप्रैल 2026 तक पुनर्नियुक्ति देने के प्रस्ताव पर नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश दिये है। सफाई दरोगा राहुल कुमार वैष्णव के नगर निगम रायपुर में संविलियन करने के प्रस्ताव की अनुशंसा करते हुए विचारार्थ राज्य शासन को भेजने का निर्णय दिया गया है। डीपीसी की बैठक 18 जून और 30 जून 2025 द्वारा नगर निगम द्वारा संचालित उ.मा. शालाओ में कार्यरत व्याख्याता प्रदीप चंद्र भोई और संध्या तिवारी को प्राचार्य पद पर पदोन्नति देने प्रस्ताव की नियमानुसार अनुशंसा कर राज्य शासन को भेजने का निर्णय लिया गया है।

महापौर मीनल चौबे की अध्यक्षता में एमआईसी ने बैठक में वित्त विभाग के प्रस्ताव अनुसार रायपुर नगर निगम के 9 कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय राशि 14 लाख 54 हजार 734 के भुगतान हेतु नियमानुसार स्वीकृति दे दी है। विद्युत विभाग के प्रस्ताव अनुसार नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न खेल मैदानो में प्रकाश व्यवस्था करने विद्युत विभाग द्वारा बुलाई गई निविदा की न्यूनतम दर 1.3 प्रतिशत बिलो 5 करोड़ 82 लाख 24 हजार 117 रुपए की निविदा समिति की अनुशंसा अनुरूप स्वीकृति दी गई है। एमआईसी ने वूमेन फॉर ट्री अंतर्गत स्वसहायता समूहो का चयन किये जाने बाबत कार्यवाही की स्वीकृति दी है। 7 स्थानों पर चयनित स्थलो पर वृक्षारोपण पौधो की देखरेख, सिंचाई एवं संधारणीय निगरानी, पौधो की जियो टैगिंग और नियमित प्रति रिपोर्टिंग चुमन फॉर ट्री अंतर्गत स्वसहायता समूहो द्वारा करने मुगतान के लिए 2 करोड़ 48 लाख 65 हजार 320 रुपए की स्वीकृति केन्द्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की अमृत मित्र योजना अंतर्गत अमृत 20 मिशन के दिशा निर्देशो के अनुरूप प्राप्त हुई है। इसे सर्वसम्मति से महापौर की अध्यक्षता ने एमआईसी ने स्वीकृति दी है।

एमआईसी की बैठक में मोटर कर्मशाला के प्रस्ताव अनुसार समस्त एमआईसी सदस्यों एवं नेताप्रतिपक्ष को चालक उपलब्ध करवाने नगर निगम समापति और महापौर हेतु नये वाहन इनोवा किस्टा उपलब्ध करवाने, मोटर कर्मशाला में 87 वाहन चालक, 2 डिप्लोमाधारी मैकेनिकल इंजीनियर, 2 मैकेनिक, 1 वेल्डर, 2 कम्प्यूटर ऑपरेटर, 1 हेल्पर प्लेसमेंट के माध्यम से उपलब्ध कराने से संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। लोककर्म विभाग जोन 9 के प्रस्ताव अनुसार वार्ड पार्षद से चर्चा अनुसार शेष बचत राशि 14 लाख 99 हजार रुपए में दया नगर आर्मी चौक के पास रोड निर्माण करने एवं जलभराव कीचड़ की समस्या दूर करने पूर्व के स्थल दलदल सिवनी ग्रामीण बैंक से अवनी विहार तक सीसी रोड निर्माण के स्थान पर स्थल परिवर्तन कर नये स्थान पर कार्य करने, पंडित विद्याचरण शुक्ल वार्ड कमांक 51 के तहत विधायक कालोनी से अविनाश वन होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 53 तक नाला निर्माण पुन: निर्माण कार्य आवश्यकता अनुसार स्थल परिवर्तन करके किये जाने प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। वहीं रानी लक्ष्मीबाई वार्ड क्रमांक 10 के आदर्श नगर गली नंबर 12 ए में सीसी रोड निर्माण के स्थान पर स्थल परिवर्तन कर रजा प्रोविजन स्टोर से मनसूर खान का घर होते हुए पटेल चार्ट अमन नगर तक सीसी सड़क निर्माण वार्ड पार्षद के पत्र अनुसार कराने स्वीकृति एमआईसी ने दी है।

महापौर मीनल चौबे की अध्यक्षता में एमआईसी ने लोककर्म विभाग के प्रस्ताव अनुसार केन्द्र सरकार की राज्य को पुंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता योजना अंतर्गत रायपुर शहर में 3 कामकाजी महिला हॉस्पिटल भैसथान में 17 करोड 23 लाख में 223 सीटर कामकाजी महिला हॉस्टल, नरैया तालाब के समीप 15 करोड़ 5 लाख में 250 सीटर कामकाजी महिला हॉस्टल, पंडरी बस स्टैण्ड के पीछे भूमि में 250 सीटर कामकाजी महिला हॉस्टल का निर्माण 15 करोड़ 10 लाख की लागत से करवाने नियमानुसार निविदा आमंत्रण कार्यवाही हेतु नियमानुसार अनुशंसा एमआईसी द्वारा की गई है। एमआईसी ने 20 करोड़ की नगर निगम रायपुर द्वारा महादेवघाट के पुनर्विकास हेतु प्रस्तावित योजना में निविदा आमंत्रण की स्वीकृति लेने प्रकरण की नियमानुसार अनुशंसा की है। पुनर्विकास योजना का उद्देश्य महादेव घाट को रायपुर का एक आदर्श धार्मिक व सांस्कृतिक पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास करना है। महापौर मीनल चौबे ने बताया कि एमआईसी ने लोककर्म विभाग के प्रस्ताव अनुसार अधोसंरचना विकास योजना अंतर्गत सिटी डेव्हलपमेंट प्लान हेतु कार्य योजना तैयार करने के संबंध में गौरव पथ 20 पचपेडी नाका से सीएसईबी चौक राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा आबंटित प्रावधान 3761 लाख रू. के अंतर्गत सभी घटको को सम्मिलित करते हुए गौरवपथ का चौडीकरण कार्य सीएसईबी से पचपेडी नाका तक रोड निर्माण कार्य करने हेतु 15 करोड की प्रस्ताव योजना की अनुशंसा नियमानुसार की है। नगरोत्थान योजना अंतर्गत सिटी डेव्हलपमेंट प्लान हेतु कार्य योजना तैयार करने राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा आबंटित प्रावधान 9300 लाख के अंतर्गत 10 करोड में 18 रोड जंक्शन आनंद नगर चौक अनुपम नगर चौक, भगत सिंह चौक, बंजारी, मोतीबाग चौक, भारत माता चौक, भारत माता चौक शंकरनगर सिविल लाईन, फाफडीह चौक, जयस्तंभ चौक, कालीबाडी चौक, खम्हारडीह थाना चौक, खजाना चौक, लाखे नगर चौक, लोधीपारा अवंति बाई चौक, महिला थाना चौक, मेक इन इंडिया चौक, राजीव गांधी सुभाष स्टेडियम चौक, शास्त्री चौक, शारदा चौक में ट्रैफिक जंक्शन को रायपुर शहर के बढ़ते यातायात दबाव को कम करने डिजाइन की गई है। उक्त अनुसार 9 करोड 98 लाख 18 हजार की स्वीकृति के प्रस्ताव एवं पृथक-पृथक निविदा आमंत्रण की अनुमति के प्रकरण की नियमानुसार अनुशंसा एमआईसी ने की है। इसी प्रकार नगरोत्थान योजना अंतर्गत सिटी डेव्हलपमेंट प्लान हेतु महादेवघाट जीर्णोद्धार कार्य हेतु 19 करोड 99 लाख 83 हजार तेलीबांधा चौक के पास टेक्नीकल टॉवर को वर्किंग स्पेस, ट्रेड एण्ड आईटी टॉवर हेतु 4 करोड 4 लाख 56 हजार, खम्हारडीह में 2500 किलोलीटर क्षमता के नवीन उच्च स्तरीय जलागार निर्माण क्लीयर वाटर राईजिंगमेन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क घरेलू नल कनेक्शन एवं पीएलसी स्काडा का कार्य करने 23 करोड 38 लाख 28 हजार का प्रस्ताव तैयार किया गया है। महापौर मीनल चौबे की अध्यक्षता में एमआईसी ने बैठक में नियमानुसार प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से अनुशंसा कर दी है।

एमआईसी ने बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य के 27 मित्र श्रेणियो में लाख 7 लाखे से अधिक दिव्यांगजनो को विशेष सुविधा चिकित्सकीय सहायता एवं केन्द्रीयकृत स्थल की आवश्यकता हेतु केन्द्रीय समाज कल्याण विभाग द्वारा दलदल सिवनी में 9 करोड 95 लाख 76 हजार 285 रू. की दिव्यांग इनक्लुजिव पार्क की दी गई स्वीकृति पर नियमानुसार निर्माण की अनुमति दलदल सिवनी अर्बन इंडस्ट्रीयल पार्क स्थल पर देने प्रक्रिया के तहत अनुशंसा दी है। एमआईसी ने शहर की महत्वपूर्ण धरोहर रायपुर के शहीद स्मारक भवन का संचालन संधारण करने आरएफपी तैयार करने एजेंसी नियुक्त किये जाने निविदा आमंत्रण हेतु लोककर्म विभाग के प्रस्ताव अनुसार नियमानुसार प्रकरण में अनुशंसा दी है।

एमआईसी ने बैठक में नगर निगम रायपुर द्वारा मोवा में गारमेंट फैक्ट्री का संचालन संधारण एवं प्रबंधन निजी एजेंसी के माध्यम से किये जाने के प्रस्ताव पर इस हेतु वार्षिक लाइसेंस शुल्क मॉडल के आधार पर तैयार आरएफपी के प्रस्ताव पर नियमानुसार स्वीकृति दे दी है। एमआईसी ने निविदा शर्तों के अनुरूप एजेंसी द्वारा न्यूनतम 500 स्थानीय महिलाओ को अनिवार्य रूप से रोजगार देना सुनिश्चित करने जिससे स्थानीय महिलाओ के मध्य रोजगार के नये अवसर उत्पन्न होंगे एवं फैक्ट्री का सदुपयोग सुनिश्चित होगा एवं रायपुर नगर निगम को वित्तीय लाम प्राप्त होगा सहित सभी शर्तें पालन करना नियमानुसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है। एमआईसी ने बैठक में रायपुर नगर निगम क्षेत्र में स्पोर्टस काम्पलेक्स आमानाका बस स्टैण्ड की 11518 वर्गमीटर गैर व्यवसायिक प्रयोजन के लिए नगर निगम रायपुर को । रू. प्रति वर्गफीट टोकन दर से आबंटन किये जाने के प्रस्ताव पर प्रकरण तैयार कर प्रशासकीय 14 करोड 26 लाख की प्रथम चरण प्राक्कलन की स्वीकृति हेतु खेल एवं युवा कल्याण विभाग के संचालक को प्रस्ताव भेजने एवं आमानाका बस स्टैण्ड की भूमि में बहुदेश्यीय स्टेडियम स्पोर्टस काम्पलेक्स निर्माण हेतु सर्वसम्मति से नगर हित में महापौर मीनल चौबे की अध्यक्षता में स्वीकृति दी है।

एमआईसी ने 26 एकड़ में फैले रायपुर के मध्य में स्थित ऐतिहासिक गंज मंडी रायपुर परिक्षेत्र का सर्वे कराकर पात्र हितग्राहियों को नवीन पुनर्विकास योजना बनाकर व्यवस्थित करने कंसलटेंट का चयन कर मास्टर प्लान बनाये जाने चरणबद्ध तरीके से पुनस्थापन प्लान तैयार करने कार्य हेतु अनुदान केन्द्र सरकार, राज्य शासन एवं अन्य रेवेन्यु शेयरिंग मॉडल अंतर्गत लाये जाने गंज मंडी परियोजना प्रस्ताव को मूर्त रूप देने की स्वीकृति नगर हित में सर्वसम्मति से दी है। एमआईसी ने 1973 में निर्माण किये गये नवीन मार्केट भवन को एक बहुद्देशीय एवं आधुनिक वाणिज्यिक परिसर के रूप में विकसित करने की आवश्यकता को देखते हुए परिसर के कुल क्षेत्रफल 4.62 एकड़ नवीन मार्केट भवन के पीछे के रिक्त भूमि और पुराने स्कूल को सम्मिलित करते हुए नई परियोजना तैयार कर मूर्त रूप देने की स्वीकृति दी है। 15 वें वित्त आयोग के तहत रायपुर अर्बन अग्लोमरेशन क्षेत्र के लिए वायु गुणवत्ता सुधार किये जाने के उपायो के संबंध में वर्ष 2024-25 में तैयार किये गये माईको एक्शन प्लांन के संबंध में 23 करोड 16 लाख के 5 प्रस्तावो को मूर्त रूप देने निविदा आमंत्रण की अनुमति एवं वित्तीय और प्रशासकीय स्वीकृति सर्वसम्मति से प्रदान की है। एमआईसी ने जोन 10 ले. अरविंद दीक्षित वार्ड क्रमांक 56 के आदर्श नगर में दुटी नाली निर्माण कार्य करने के प्रकरण में जोन 10 जोन अध्यक्ष के पत्र अनुसार स्थल परिवर्तन कर बजाज कालोनी सेक्टर 1 अनमोल प्रोविजन स्टोर के पास नाली निर्माण कराये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।

एमआईसी ने जोन 8 शहीद भगत सिंह वार्ड क्रमांक 21 के तहत स्थित छुईया तालाब हेतु छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा दी गई 2 करोड़ 96 लाख 28 हजार की स्वीकृति के आधार पर छुईया तालाब का सौंदर्याकरण कार्य कराये जाने नियमानुसार निविदा आमंत्रण करने की स्वीकृति सर्वसम्मति से जनहित में दी है। एमआईसी ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 अंतर्गत 10 सीटर आकांक्षीय शौचालयो का निर्माण कार्य 10 स्थानो तेलीबांधा तालाब के पास, स्वामी विवेकानंद सरोवर के पास, कटोरा तालाब के पास, काली माता मंदिर के पास, महामाया मंदिर के पास, बस स्टैण्ड के पास, राममंदिर के पास, नालंदा परिसर के पास, खाटु श्याम मंदिर के पास, जगन्नाथ मंदिर के पास कराने 2 करोड 42 लाख की लागत से दी गई शासन की स्वीकृति एवं ई टेण्डर कार्यवाही उपरांत रायपुर नगर निगम द्वारा स्वीकृति अनुरूप 282 लाख के अतिरिक्त लागत का वहन नगर निगम द्वारा किये जाने की शर्त पर 2 करोड 96 लाख 22 हजार के कार्यों हेतु दर अनुमोदन अनुबंध कार्यादेश हेतु नियमानुसार प्रस्ताव अनुसार जनहित में सर्वसम्मति से स्वीकृति दी है। स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत 3 स्थानो दूधाधारी मठ के पास, एनर्जी पार्क के पास, महादेवघाट के पास 50 लाखप 76 हजार की लागत से 6 सीटर आकांक्षीय शौचालयो का निर्माण किये जाने प्रस्ताव अनुसार नियमानुसार स्थल परिवर्तन की स्वीकृति दी है। प्रकरण में एनर्जी पार्क के स्थल पर बंजारी माता मंदिर पंडित रविशंकर शुक्ल युनिवर्सिटी परिसर महादेवघाट के स्थान पर ठाकुर प्यारेलाल सिंह वार्ड मंगल बाजार क्षेत्र में स्थल परिवर्तन कर नवीन स्थल पर 6 सीटर आकांक्षीय शौचालय निर्माण करने नियमानुसार अनुशंसा एमआईसी ने कर दी है।

एमआईसी ने स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत प्रस्ताव अनुसार मशीनीकृत सडक सफाई कार्य के मूल अनुबंध 13 जुलाई 2021 की स्वीकृत दर पर अतिरिक्त नवीन चिन्हित सडको की मशीनीकृत सडक सफाई कार्य की नियमानुसार स्वीकृति दे दी है। मूल अनुबंध की शेष अवधि मई से अगस्त 2025 तक नवीन प्रस्तावित 19 सडको 66.19 किलोमीटर क्षेत्र की मशीनीकृत सफाई कार्य संस्था मेसर्स ग्लोबल गुज वेस्ट मैनेजमेंट एलएलपी से कराये जाने स्वीकृति दी है। उक्त संस्था को मशीनीकृत सडक सफाई कार्य के मूल अनुबंध दिनांक 13 जुलाई 2021 की कंडिका के प्रावधान अनुसार कार्य में 2 वर्ष की अतिरिक्त समयावधि और संभावित व्यय 51 करोड़ 88 लाख 28 हजार 7 रू. की नियमानुसार अनुशंसा एमआईसी ने करते हुए प्रकरण को स्वीकृति हेतु राज्य शासन को भेजने के निर्देश दिये है। एमआईसी की बैठक के दौरान महापौर मीनल चौबे ने नगर निगम के सभी जोन कमिश्नरो को जोन क्षेत्र के वार्डो के मुख्य मार्गों में आवारा पशुओ की धरपकड करने, सड़को पर हुए गड्ढो की मरम्मत एवं आवश्यक सुधार जनहित में करने एवं सड़को पर अवैध अतिक्रमणो को नियमानुकुल कडाई के साथ हटाने की कार्यवाही हेतु अभियान चलाने के आवश्यक निर्देश दिये है। आयुक्त विश्वदीप ने जोन कमिश्नरो को एमआईसी की बैठक में महापौर मीनल चौबे द्वारा दिये गये निर्देशो का जनहित की दृष्टि से कडाई से पालन सुनिश्चित करने निर्देशित किया है।

बैंकिंग को केवल सेवा नहीं, बल्कि एक अनुभव बनाने की दिशा में सभी को देना चाहिए योगदान

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। पंजाब एंड सिंध बैंक शुरू की गई नवीन पहलों जैसे कि डिजिटल बैंकिंग सुविधाएं, नवीन उत्पाद योजनाएं, एमएसएमई क्षेत्र को दिए जा रहे वित्तीय सहयोग, तथा समावेशी बैंकिंग प्रयासों की विस्तृत जानकारी साझा करते हुए प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्वरूप कुमार साहा कहा कि बैंक ने ग्राहकों तक पहुंच बढ़ाने और उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप सेवाएं प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।

बैंकिंग उत्पादों, ग्राहक सेवा गुणवत्ता और डिजिटलीकरण की दिशा में हो रहे नवाचारों के साथ ही बैंकिंग को केवल सेवा नहीं, बल्कि एक अनुभव बनाने की दिशा में सभी को योगदान देना चाहिए। इस दौरान उन्होंने बैंक के बर्तमान और भविष्य के रणनीतिक दृष्टिकोण पर पत्रकारों से जानकारी साझा किया। इस अवसर पर बैंक के वरिष्ठ अधिकारी स्वरूप दास गुप्ता (वित्तीय सलाहकार), राजेन्द्र कुमार रैगर (महाप्रबंधक) तथा श्री तारा चंद मीणा (आंचलिक प्रबंधक, भोपाल) के अलावा बैंक के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।

उन्होंने बताया कि ग्राहकों से प्रत्यक्ष संवाद कर उनकी बैंकिंग आवश्यकताओं, सुझावों और अपेक्षाओं को जानने के लिए वे छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे है। इसी परिप्रेक्ष्य में कल वे बिलासपुर गए थे और रायपुर में ग्राहकों से मिलकर उनकी जिज्ञासाओं में जाना और उनकी प्रतिक्रिया के आधार पर सेवाओं में सुधार किया जा रहा है। इससे पूर्व उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से उनके निवास में मुलाकात कर बैंक से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। उन्होंने यह भी बताया कि रायपुर जैसे उभरते शहरी केंद्रों में बैंक अपनी उपस्थिति को और अधिक सशक्त बनाने हेतु कार्य कर रहा है, ताकि क्षेत्रीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को गति दी जा सके।

भोजली माता से सामूहिक सेवाअर्जी करने इंडोर स्टेडियम में जुटेंगे गोड़ी धर्मी

रायपुर। गोंडी धर्म संस्कृति संरक्षण समिति एवं छत्तीसगढ़ गोंडवाना संघ जिला इकाई के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय भोजली महोत्सव एवं विश्व आदिवासी दिवस समारोह के तहत भोजली माता से सामूहिक सेवाअर्जी करने हजारों गोड़ी धर्मी बलवीर सिंह जूनेजा इंडोर स्टेडियम रायपुर में जुटेंगे। इस समारोह में छत्तीसगढ़ राज्य के अलावा मध्यप्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तरप्रदेश, झारखण्ड, सिक्किम व तेलंगाना राज्य सहित अन्य राज्यों के भी समाज प्रमुख, प्रबुद्धजन लाखों की संख्या में शामिल होंगे। गोंडी धर्म संस्कृति संरक्षण समिति के अध्यक्ष तिरु. चंद्रभान (बल्लू नेताम), प्रांतीय महासचिव तिरू. प्रीतम छेदैहा, मीडिया प्रभारी अश्वनी छेदैहा ने संयुक्त पत्रकारवार्ता में बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 9 अगस्त को विश्व आदिवासी घोषित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने माना है कि विश्व के करीब 195 देशों में से 90 देशों मे 5 हजार आदिवासी समुदाय जिनकी संख्या करीब 38 करोड़ है उनकी अपनी 7000 भाषाए है। बावजूद आज भी इनके अधिकारों का सबसे ज्यादा हनन हो रहा है। गोंडी धर्म संस्कृति संरक्षण समिति एवं छत्तीसगढ़ गोंडवाना संघ जिला इकाई इसकी भर्त्सना व निंदा करते हुए देश की न्याय पालिका व जिम्मेदार व्यक्ति से पदीय गरिमा के अनुरुप नैतिकता के आधार पर न्याय की अपेक्षा करते है।

हर घर तिरंगा अभियानः गनियारी की दीदियां जुटीं तिरंगा निर्माण में मिला डेढ़ लाख झंडों का ऑर्डर

रायपुर। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान जोर-शोर से चलाया जा रहा है। इसी क्रम में बिलासपुर जिले के गनियारी स्थित नारी शक्ति गारमेंट फैक्ट्री देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आ रहा है, जहां बिहान योजना से जुड़ी 30 स्व-सहायता समूहों की 100 से अधिक महिलाएं तिरंगा निर्माण में पूरी लगन से जुटी हुई हैं। इन दीदियों को 1.50 लाख से अधिक तिरंगे तैयार करने का ऑर्डर मिला है, जो जिले के शासकीय व अशासकीय संस्थानों सहित आम नागरिकों को उपलब्ध कराए जाएंगे। बढ़ती मांग को देखते हुए महिलाएं इस जिम्मेदारी को उत्साहपूर्वक निभा रही हैं।न केवल यह कार्य उनके लिए अतिरिक्त आय का जरिया बना है, बल्कि राष्ट्र सेवा से जुड़ने का अवसर भी प्रदान कर रहा है।

मालविका मोहनन को जन्मदिन का तोहफा, मेकर्स ने रिलीज किया द राजासाब से उनका फर्स्ट लुक

अभिनेता प्रभास काफी समय से फिल्म द राजा साब को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। उनकी इस फिल्म के निर्देशन की कमान साउथ के जाने-माने निर्देशक मारुथि ने संभाली है। इस फिल्म में प्रभास के साथ अभिनेत्री मालविका मोहनन नजर आएंगी. मालविका के जन्मदिन पर उनके प्रशंसकों को बड़ा तोहफा मिला है। दरअसल, फिल्म द राजा साब से मालविका की पहली झलक सामने आ गई है।

सामने आए पोस्टर में मालविका सफेद संग की साड़ी पहने नजर आ रही हैं, जिसमें वह बेहद खूबसूरत लग रही हैं। इस फिल्म में प्रभास और मालविका के अलावा निधि अग्रवाल, संजय दत्त और रिद्धि कुमार जैसे कलाकार भी नजर आएंगे। द राजा साब पहले इस साल 10 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी, लेकिन बाद में इसे 5 दिसंबर, 2025 के लिए टाल दिया गया। अब कहा जा रहा है कि यह फिल्म 9 जनवरी, 2026 को रिलीज होगी।

मालविका एक भारतीय अभिनेत्री हैं, जो मुख्य रूप से तमिल और मलयालम फिल्मों में काम करती हैं। मालविका ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत साल 2013 में आई मलयालम फिल्म पट्टम पोल के जरिए की थी। उन्होंने निर्णयम, नानु मट्टु वरलक्ष्मी, थंगालान, मारन, क्रिस्टी और मास्टर जैसी फिल्मों में भी काम किया है। मालविका ने बियॉन्ड द क्लाउड्स के जरिए बॉलीवुड में कदम रखा था, जिसमें उनकी जोड़ी ईशान खट्टर के साथ बनी थी। यह फिल्म 20 अप्रैल, 2018 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी। मालविका फिल्म युद्धरा में भी काम कर चुकी हैं, जिसके हीरो सिद्धांत चतुर्वेदी हैं। हालांकि, यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर मुंह के बल गिरी। यह फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है।

अमृता खानविलकर को पहला महाराष्ट्र स्टेट फिल्म अवॉर्ड मिला, बोलीं- मैं इसे कभी नहीं भूल पाऊंगी

अमृता खानविलकर को पहला महाराष्ट्र स्टेट फिल्म अवॉर्ड मिला, बोलीं- मैं इसे कभी नहीं भूल पाऊंगी

अमृता खानविलकर मराठी और हिंदी फिल्मों की जानी-मानी अभिनेत्री हैं। उन्हें हाल ही में महाराष्ट्र स्टेट फिल्म अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है। 60-61वें महाराष्ट्र स्टेट फिल्म अवॉर्ड का कार्यक्रम हाल ही में हुआ था, जिसमें एक्ट्रेस को फिल्म चंद्रमुखी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड दिया गया।

एक्ट्रेस अभी भारत में नहीं हैं, लेकिन उन्होंने एक बयान जारी करते हुए कहा, आज का दिन मेरे लिए खास है क्योंकि महाराष्ट्र राज्य ने मुझे नई पहचान दी है। हमने चंद्रमुखी में एक टीम की तरह काम किया और डायरेक्टर से लेकर स्पॉट बॉय तक, हमारी कड़ी मेहनत रंग लाई। दर्शकों ने इसे जो प्यार दिया, वो आज भी दिखता है।

अमृता ने कहा, एक एक्ट्रेस के रूप में मुझे जो नई पहचान मिली है चंद्रमुखी के लिए, उसके लिए मैं महाराष्ट्र राज्य की शुक्रगुजार हूं। इस पल को मैं कभी नहीं भुला पाऊंगी, ये मेरा पहला स्टेट अवॉर्ड है। यह पुरस्कार मुझे मेरे काम को नई ऊर्जा से और भी गुणवत्तापूर्वक करने के लिए प्रेरित करेगा।

अमृता ने जूरी और महाराष्ट्र स्टेट फिल्म अवॉर्ड्स की टीम को दिल से धन्यवाद कहा। चंद्रमुखी फिल्म में अमृता के साथ आदिनाथ कोठारे लीड रोल में हैं। इस फिल्म को प्रसाद ओक ने डायरेक्ट किया है।

महाराष्ट्र स्टेट फिल्म अवॉर्ड्स राज्य सरकार देती है, जो मराठी भाषा की फिल्म और कलाकारों को मिलते हैं। इनकी शुरुआत 1963 में हुई थी। महाराष्ट्र स्टेट फिल्म अवॉर्ड्स सांस्कृतिक कार्य विभाग, महाराष्ट्र सरकार से गठित एक स्वतंत्र जूरी तय करती है।

एक स्पेशल जूरी भी होती है, जो सिनेमा पर अच्छे लेख लिखने वालों को भी सम्मानित करती है। इस अवॉर्ड का उद्देश्य सिनेमा में कलात्मक उत्कृष्टता को बढ़ावा देना तथा फिल्म निर्माताओं, तकनीशियनों और निर्माताओं को प्रोत्साहित करना है।

बेहतरीन आवाज की मालकिन तो डांसिंग में शानदार, बेहद ग्लैमरस है आकृति कक्कड़

जब बात दिल को छू लेने वाली आवाज और मंच पर थिरकते कदमों की हो, तो बॉलीवुड में एक नाम जो तुरंत जेहन में आता है, वो आकृति कक्कड़ का है। 7 अगस्त को जन्मीं सिंगर ने सुरीली आवाज और बिंदास अंदाज से लाखों दिलों में जगह बनाई है।

आकृति कक्कड़ ने अपने करियर की शुरुआत छोटे-छोटे कदमों से की, लेकिन उनकी प्रतिभा ने उन्हें बॉलीवुड के बड़े प्लेटफॉर्म तक पहुंचा दिया। दिल्ली में जन्मीं और पली-बढ़ी आकृति ने संगीत की दुनिया में कदम रखते ही सबका ध्यान खींच लिया। उनके हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया में गाए गाने सैटरडे सैटरडे और 2 स्टेट्स के इसकी उसकी ने न सिर्फ चार्टबस्टर्स पर राज किया, बल्कि युवाओं की प्लेलिस्ट में भी जगह बनाई। इन गानों में उनकी एनर्जी और मस्ती ने हर किसी को झूमने पर मजबूर कर दिया। इसके अलावा, खुदाया खैर और आज दिन चढ़ेया जैसे गाने उनकी गायकी की गहराई को दिखाते हैं। आकृति ने न सिर्फ बॉलीवुड में अपनी छाप छोड़ी, बल्कि अप्रैल 2010 में अपने सोलो एल्बम आकृति को रिलीज कर एक नया मुकाम हासिल किया। इस एल्बम में शंकर महादेवन के साथ मिलकर उन्होंने गीतों को कंपोज भी किया, जो उनकी कला को और भी शानदार अंदाज में पेश करता है। उनके गाए माशा अल्लाह गाने को भी काफी पसंद किया गया। हालांकि, उनका गाना रिंग डायमंड दी विवादों में भी रहा, जब इसे गर्ल्स जेनरेशन के कुछ गानों से प्रेरित होने का आरोप लगा।

आकृति न सिर्फ अपनी आवाज, बल्कि अपने डांस और ग्लैमरस अंदाज के लिए भी जानी जाती हैं। अपने बेटे के जन्म के महज 20 दिन बाद मंच पर नंगे पांव बलम पिचकारी गाते हुए उनकी एनर्जेटिक परफॉर्मेंस ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। उनकी परफॉर्मेंस को खूब पसंद किया गया। आकृति ने खुद कहा, ताकत अप्रत्याशित जगहों से मिलती है और मुझे ये मेरे छोटे बच्चे से मिली। आकृति की दो बहनें, सुकृति और प्राकृति कक्कड़ भी प्लेबैक सिंगर हैं, और तीनों बहनों ने मिलकर संगीत की दुनिया में एक से बढ़कर एक गाने दिए हैं। आकृति ने साल 2016 में डायरेक्टर चिराग अरोड़ा से शादी की और साल 2023 में बेटे को जन्म दिया। वह अपनी पर्सनल लाइफ को निजी रखना पसंद करती हैं, लेकिन फैंस के लिए सोशल मीडिया पर अपनी और परिवार की तस्वीरें पोस्ट करती रहती हैं।

जन्नत गर्ल अपनी खूबसूरत अदाओं से बरपा रही कहर, भले ही फिल्मों से दूर, लेकिन चर्चा भरपूर

बॉलीवुड जगत एक रंगीन दुनिया का रंगीन ख्वाब है, यहां पर कई अभिनेत्रियां और अभिनेता डेब्यू करते नजर आते है, लेकिन कुछ ही कलाकार रातों रात उपलब्धि पा लेते है। आज हम बात कर रहे हैं जन्नत गर्ल की, जी हां बॉलीवुड मूवी जन्नत में अभिनय करके अभिनेत्री सोनम चौहान जन्नत गर्ल के नाम से पॉपुलर हुई थी।

भले ही आज सोनम चौहान की अपकमिंग मूवीज के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर उनका जलवा बरकरार है। जी हां सोनम चौहान अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी हॉट फोटोज और वीडियो शेयर करती रहती है। जिन्हे उनके फैंस वीडियोज और फोटोज पर लाइक और कमेंट करते नजर आते है। आपको बता दें कि पहली मूवी करते ही सोनम चौहान नेशनल क्रश बन गई थी और जन्नत गर्ल के नाम से पॉपुलर हुई।

बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस सोनल चौहान ने वर्ष 2008 में आई इमरान हाशमी की मूवी जन्नत से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। अभिनेत्री अपनी डेब्यू मूवी से ही रातों रात स्टार बन गई थीं। अभिनेता इमरान हाशमी स्टारर जन्नत रिलीज होने के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। इस मूवी के बाद सोनल चौहान को जन्नत गर्ल का टैग मिल गया था। उन्होंने बॉलीवुड के अलावा साउथ मूवीज में भी काम किया है। गत माह आईपीएल मैच का लुत्फ उठाते जन्नत गर्ल की कई फोटोज वायरल हुई थीं। फिलहाल उनकी अपकमिंग

मूवीज के बारे में कोई जानकारी नहीं है। आज भले ही सोनल मूवीज में कम नजर आती हो, लेकिन वो सोशल मीडिया पर खासा सक्रिय रहती हैं और फैंस संग अपनी फोटोज और वीडियो शेयर करती नजर आती है।

चुकंदर से बनता है स्वादिष्ट और पौष्टिक सूप, जानिए इसके फायदे और रेसिपी

सूप एक ऐसा व्यंजन है, जो स्वाद के साथ-साथ सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। अगर आप रोजाना एक कटोरी सूप का सेवन करते हैं तो इससे आपके शरीर को कई जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं। वहीं अगर सूप की बात करें तो चुकंदर से बना सूप एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। आइए जानते हैं कि चुकंदर से बना सूप कैसे बनाया जाता है और इसके सेवन से क्या-क्या स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं।

चुकंदर के सूप को बनाने का तरीका

सबसे पहले चुकंदर को छीलकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें और बाकी सब्जियों को भी इसी तरह काट लें। अब एक पैन में मक्खन या घी गर्म करें और उसमें अदरक-लहसुन पेस्ट और प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनें। इसके बाद इसमें टमाटर और गाजर डालकर कुछ मिनट पकाएं, फिर इसमें चुकंदर डालें और पानी मिलाकर इसे मध्यम आंच पर पकने दें। जब सब्जियां नरम हो जाएं तो सूप को पीस लें और नींबू का रस मिलाकर गर्मागर्म परोसें।

रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देने में है सहायक

चुकंदर से बना सूप रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। इसमें ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर की सुरक्षा को मजबूत करने में सहायक होते हैं। नियमित रूप से चुकंदर का सूप पीने से आप मौसमी बुखार, खांसी-जुकाम और अन्य संक्रमण से बच सकते हैं। इसके अलावा इसमें मौजूद तत्व प्रतिरोधक क्षमता को मजबूती देने में मदद करते हैं।

पाचन क्रिया को कर सकता है सुधार

चुकंदर से बना सूप पाचन के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। इसमें फाइबर होता है, जो पाचन को सुधारने में मदद करता है। फाइबर खाने को पचाने में मदद करता है और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाता है। इसके अलावा चुकंदर में मौजूद तत्व पाचन को बेहतर बनाने में सहयोग प्रदान करते हैं। इसलिए डाइट में चुकंदर के सूप को शामिल करना लाभदायक हो सकता है।

वजन प्रबंधन में है कारगर

अगर आप अपने वजन को नियंत्रित करना चाहते हैं तो इसके लिए भी चुकंदर का सूप फायदेमंद हो सकता है। इसमें कैलोरी कम होती है और फाइबर अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो आपको लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है। इससे आप बार-बार खाने से बच सकते हैं और आपका वजन नियंत्रित रहता है। इसके अलावा इसमें मौजूद पोषक तत्व शरीर की ऊर्जा को तेज करते हैं, जिससे शरीर अतिरिक्त चर्बी को जल्दी जलाता है।

त्वचा के लिए भी है फायदेमंद

चुकंदर में मौजूद तत्व त्वचा के लिए भी फायदेमंद होते हैं। ये त्वचा की कोशिकाओं को बचाते हैं, जो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को तेज करते हैं। इसके अलावा चुकंदर में मौजूद तत्व त्वचा की रंगत को सुधारने में मदद करते हैं। नियमित रूप से चुकंदर का सूप पीने से त्वचा में निखार आता है और वह स्वस्थ रहती है। इसलिए इसे अपनी डाइट में शामिल करना लाभदायक हो सकता है।

दिल के स्वास्थ्य के लिए है अच्छा

चुकंदर का सूप दिल के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। इसमें ऐसे तत्व होते हैं, जो रक्त संचार को बेहतर बनाते हैं और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखते हैं। इसके अलावा इसमें ऐसे तत्व होते हैं, जो दिल की बीमारी के खतरे को कम करते हैं। नियमित रूप से चुकंदर का सूप पीने से आपका दिल स्वस्थ रहता है और आप कई बीमारियों से बचे रहते हैं। इसलिए इसे अपनी डाइट में शामिल करना लाभदायक हो सकता है।

समंदर किनारे एक्ट्रेस आरती सिंह ने लगाई आग, बोल्ड बिकिनी में फ्लॉन्ट किया अपना फिगर, फोटोज वायरल

टीवी की मशहूर अदाकारा एक्ट्रेस आरती सिंह अक्सर अपनी फोटोज से इंटरनेट पर तहलका मचा देती हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने अपनी लेटेस्ट बिकिनी फोटोज शेयर की, जिससे सोशल मीडिया पर आग लग गया। लोग उनकी फोटोज पर भरपूर प्यार लुटा रहे हैं। फोटोज में आरती अपनी टोन्ड बॉडी को फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं।

एक्ट्रेस आरती सिंह ने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी हॉट तस्वीरें शेयर की हैं। फोटोज में एक्ट्रेस को बिकिनी में देखा जा सकता है। हॉट अवतार में समंदर किनारे आरती बेहद ही खूबसूरत और बोल्ड लग रही हैं।

पोस्ट करते ही उनकी ये तस्वीरें वायरल हो गई। कमेंट सेक्शन में फैंस उनकी खूब तारीफें कर रहे हैं। एक्ट्रेस ने ये फोटोज अपने मालदीव वेकेशन से शेयर की हैं। फैंस इसपर जमकर प्यार लुटा रहे हैं। इस फोटोज में आरती ग्रीन स्लीपलेस स्विमसूट में कहर ढा रही हैं। स्टाइलिश पोज देते कड़ी आरती का लुक हर किसी का दिल जीत ले रहा है।

सोशल मीडिया पर आरती सिंह ने ऐसी अपनी कई फोटोज शेयर की हैं। इस तस्वीर में एक्ट्रेस ने स्विमसूट को व्हाइट स्कर्ट के साथ पेयर किया है। सनग्लासेस पहने वो काफी हॉट लग रही हैं। बता दें कि आरती सिंह ने बॉयफ्रेंड दीपक चौहान से 25 अप्रैल 2024 को मुंबई के इस्कॉन मंदिर में शादी की थी। आरती सुपरस्टार गोविंदा की भांजी और कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक की बहन भी लगती हैं।

बता दें कि आरती सिंह ने बॉयफ्रेंड दीपक चौहान से 25 अप्रैल 2024 को मुंबई के इस्कॉन मंदिर में शादी की थी। आरती सुपरस्टार गोविंदा की भांजी और कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक की बहन भी लगती हैं। सोशल मीडिया पर आरती काफी एक्टिव रहती हैं। यहां वो अक्सर अपनी तस्वीरें और विडियोज शेयर करती रहती हैं। उनकी तस्वीरें काफी तेजी से वायरल हो जाती हैं।

टीवी की दुनिया में अपने शानदार किरदार से आरती हर किसी का दिल जीत चुकी हैं। आरती सिंह अब तक कई टीवी शोज का हिस्सा रह चुकी हैं। उन्होंने मायका, गृहस्थी, थोड़ा है बस थोड़े की जरूरत है, परिचय, उतरन, देवों के देवज्महादेव और ससुराल सिमर का में काम किया है।

अपनी साधारण सैंडल्स को बदलना चाहते हैं? आजमाएं ये आसान तरीके

सैंडल्स हमारे रोजमर्रा के जीवन का अहम हिस्सा हैं। ये आरामदायक होने के साथ-साथ हमारे स्टाइल को भी पूरा करती हैं, लेकिन कई बार ये उबाऊ लगने लगती हैं। ऐसे में कुछ छोटे-छोटे बदलाव करके आप अपनी पुरानी सैंडल्स को नया रूप दे सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपनी साधारण सैंडल्स को आकर्षक बना सकते हैं। इन तरीकों से आप अपने पैरों को स्टाइलिश बना सकते हैं।

मोती और स्टोन का उपयोग करें

मोती और स्टोन का उपयोग करके आप अपनी सैंडल्स को बहुत ही आकर्षक बना सकते हैं। इसके लिए आपको बस कुछ छोटे-छोटे मोती या स्टोन चाहिए, जिन्हें आप सैंडल्स के पट्टे पर चिपका सकते हैं। आप इन्हें गोंद की मदद से चिपका सकते हैं या फिर सिलाई कर सकते हैं। यह तरीका न केवल आपकी सैंडल्स को नया रूप देगा, बल्कि इसे पहनने पर आपको खास महसूस होगा।

रिबन और लेस जोड़ें

रिबन और लेस जोड़कर भी आप अपनी साधारण सैंडल्स को स्टाइलिश बना सकते हैं। इसके लिए आप किसी रंगीन या डिजाइनदार रिबन का चयन करें और उसे सैंडल्स के पट्टे पर बांधें। इससे आपकी सैंडल्स में एक नया टच आएगा। इसके अलावा आप लेस का भी उपयोग कर सकते हैं, जिससे सैंडल्स को एक अलग ही लुक मिलेगा। यह तरीका न केवल देखने में अच्छा लगेगा बल्कि पहनने में भी

आरामदायक होगा।

फूलों का उपयोग करें

फूलों का उपयोग करके भी आप अपनी पुरानी सैंडल्स को नया रूप दे सकते हैं। इसके लिए आप नकली फूल खरीद सकते हैं या फिर अपने पुराने कपड़ों से काटकर उपयोग कर सकते हैं। इन फूलों को सैंडल्स के पट्टे पर चिपकाएं या सिलाई करें। इससे आपकी सैंडल्स न केवल आकर्षक दिखेंगी बल्कि इन्हें पहनकर चलने में भी मजा आएगा। यह तरीका आपके पैरों को स्टाइलिश बनाने में मदद करेगा और आपके लुक को खास बनाएगा।

पेंटिंग करें

अगर आप थोड़े रचनात्मक हैं तो आप पेंटिंग का सहारा ले सकते हैं। इसके लिए आपको कपड़ों पर रंग लगाने वाला रंग चाहिए होगा, जिसे आप अपनी पसंदीदा डिजाइन में सैंडल्स पर पेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्टेंसिल का भी उपयोग कर सकते हैं, जिससे आपकी सैंडल्स में एक नया टच आएगा। इस तरह आप अपनी पुरानी सैंडल्स को आसानी से नया रूप दे सकते हैं और उन्हें स्टाइलिश बना सकते हैं।

दो से अधिक बार शराब तस्करी पर होगी संपत्ति जब्ती की कार्रवाई : उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा

- सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में शीघ्र शुरू हो ओपीडीः विजय शर्मा
- ग्राम पंचायतों की आय बढ़ाने कॉम्प्लेक्स निर्माण का सुझाव, मक्का व मिलेट्स किसानों को मिलेगा प्रोत्साहन
- मनरेगा, पीएम आवास, महतारी वंदन से लेकर जल जीवन मिशन तक सभी योजनाओं की गहन समीक्षा

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। उपमुख्यमंत्री एवं बस्तर जिले के प्रभारी मंत्री विजय शर्मा ने जगदलपुर स्थित जिला कार्यालय के प्रेरणा सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा जिले में किए जा रहे नवाचारों और योजनाओं के क्रियान्वयन की गहन समीक्षा की उपमुख्यमंत्री शर्मा ने स्पष्ट निर्देश दिए कि यदि कोई व्यक्ति दो से अधिक बार शराब या अन्य नशे की तस्करी में संलिप्त पाया जाता है, तो उसकी संपत्ति जब्त करने की कानूनी कार्यवाही तत्काल आरंभ की जाए। उन्होंने नशा उन्मूलन के लिए पुलिस विभाग, जनप्रतिनिधियों और दवा व्यापारियों के साथ समन्वय बैठक आयोजित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने जगदलपुर के सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में शीघ्र ओपीडी सेवा प्रारंभ करने को कहा, ताकि आम जनता को विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाएं सुलभ हो सकें।

उपमुख्यमंत्री ने राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे स्थित ग्राम पंचायतों में कॉम्प्लेक्स निर्माण कर पंचायतों को स्वावलंबी बनाने का सुझाव दिया, जिससे पंचायतों को स्थायी राजस्व प्राप्त हो सके। उन्होंने पंचायत सचिवों को अविवादित बंटवारे के मामलों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने हेतु ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण देने और जनजागरूकता हेतु मुनादी एवं होर्डिंग लगाने के निर्देश भी दिए। मिलेट्स उत्पादन करने वाले किसानों के उत्पाद को बाजार तक पहुँचाने की ठोस व्यवस्था बनाने तथा मक्का उत्पादक किसानों को स्प्रिंकलर एवं विभागीय योजनाओं से जोड़ने की बात भी कही।

बैठक में पंचायत विभाग द्वारा किए गए नवाचारों, अटल डिजिटल सुविधा केंद्र, महतारी सदन, दीनदयाल अंत्योदय योजना, बिहान, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), आत्मसमर्पित नक्सली एवं नक्सल पीड़ित हितग्राहियों को प्रथम किश्त के उपरांत आवास की प्रगति, ग्राम पंचायतों में पंजी संधारण की स्थिति, डीपीआरसी ट्रेनिंग सेंटर, स्वच्छ भारत मिशन तथा आगामी तीन माह की कार्ययोजना की भी समीक्षा की गई।

उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने गृह विभाग के अंतर्गत अवैध शराब, सट्टा, जुआ, गोधन तस्करी, यातायात नियंत्रण, हिट एंड रन, मोटरयान अधिनियम की धाराओं पर की गई कार्रवाई, ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन, गुम इंसानों के प्रकरण और एनडीपीएस एक्ट के मामलों की स्थिति की जानकारी ली गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए गए नवाचारों, आयुष्मान कार्ड वितरण, मोबाइल हेल्थ वैन संचालन, जनऔषधि केंद्रों की उपलब्धता, सिकलसेल डायग्नोसिस, डॉक्टरों और पैरा मेडिकल स्टाफ की स्थिति तथा आगामी तीन माह के लिए निर्धारित कार्ययोजना की समीक्षा की गई।

वन विभाग द्वारा किए गए लाख उत्पादन, तेंदूपत्ता बोनस वितरण, चरण पादुका वितरण और निर्माण कार्यों की स्थिति की समीक्षा के साथ-साथ कैंपा मद में दो वर्षों के आवंटन और व्यय की जानकारी भी ली गई। महिला एवं बाल विकास विभाग की महतारी वंदन योजना, मातृ वंदन योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, स्वस्थ लड़का अभियान और नीति आयोग के सहयोग से चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों की अद्यतन स्थिति की जानकारी भी बैठक में दी गई। राजस्व विभाग द्वारा किए गए नवाचार, प्रकरणों की स्थिति, शिविरों की प्रगति और भू-अर्जन से संबंधित कार्यों की समीक्षा की गई। कृषि विभाग द्वारा रकबा, बीज एवं उर्वरक वितरण, आत्मा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, खरीफ की तैयारी, चौम्प्स योजना से यंत्र वितरण आदि की अद्यतन जानकारी ली गई। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत घरेलू नल कनेक्शन, पूर्णता प्रमाण पत्र और हर घर जल प्रमाणीकरण की स्थिति पर चर्चा हुई।

उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने जल संसाधन विभाग के तहत प्रमुख बांध, नहर और जलाशयों में जलभराव की स्थिति की समीक्षा की गई। विद्युत विभाग की प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, ट्रांसफार्मर की उपलब्धता, आरडीएसएस योजना के तहत क्रियान्वयन की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया गया। लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा तथा राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्यों और आगामी तीन माह के कार्यों की कार्ययोजना पर भी चर्चा हुई।

शिक्षा विभाग द्वारा ज्ञानगुड़ी योजना के तहत निरूशुल्क कोचिंग, आईसीटी आधारित प्रशिक्षण, बहुभाषी शिक्षा, पीएम श्री स्कूलों के निर्माण, शिक्षा गुणवत्ता कार्यक्रम, मिशन 200, जीरो ड्रॉपआउट अभियान और सम्पर्क फाउंडेशन की गतिविधियों की समीक्षा की गई। आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा छात्रावासों और छात्रवृत्तियों की स्थिति प्रस्तुत की गई। खाद्य विभाग द्वारा पीडीएस प्रणाली, धान भंडारण एवं उठाव की स्थिति की जानकारी दी गई। नगर निगम द्वारा स्वच्छ भारत मिशन शहरी, पीएम आवास योजना शहरी, भवन अनुज्ञा एवं अधोसंरचना विकास कार्यों की समीक्षा की गई। जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र द्वारा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना और पीएमईजीपी की प्रगति की जानकारी प्रस्तुत की गई। इसके अतिरिक्त सहकारिता, समाज कल्याण और श्रम विभाग की गतिविधियों की भी समग्र समीक्षा की गई।

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित की जाए तथा यह ध्यान रखा जाए कि इन योजनाओं का लाभ अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि विकास के कार्यों में शिथिलता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में चित्रकोट विधायक विनायक गोयल, महापौर संजय पांडेय, सचिव पंचायत भीम सिंह, कलेक्टर हरिस एस., पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा, जिला पंचायत सीईओ प्रतीक जैन, वनमंडलाधिकारी उत्तम गुप्ता सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

पीएम जनमन योजना के तहत छत्तीसगढ़ को मिली 375 करोड़ से अधिक के लागत की 100 पुलों की स्वीकृति

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को 375.71 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 6,569.56 मीटर लम्बाई के कुल 100 पुलों की स्वीकृति प्रदान की गई है। यह स्वीकृति 2025-26 बैच –II के अंतर्गत दी गई है।

इस ताज़ा स्वीकृति के साथ अब तक राज्य को कुल 715 सड़कें (2,449.108 किलोमीटर) और 100 पुल प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत स्वीकृत किए जा चुके हैं। इस स्वीकृति पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया है।

उन्होंने कहा कि जन-मन योजना के माध्यम से विशेष रूप से कमजोर जनजातीय

समूहों को सशक्त बनाने की जो दूरदर्शी पहल केंद्र सरकार द्वारा की गई है, वह छत्तीसगढ़ जैसे आदिवासी बहुल राज्य के लिए महत्वपूर्ण है। हम इस स्वीकृति को केवल पुलों और सड़कों की स्वीकृति नहीं, बल्कि विकास, विश्वास और समावेश की नई राह के रूप में देखते हैं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार की भावना के अनुरूप इन सभी स्वीकृत कार्यों को फास्ट ट्रैक मोड पर, पूर्ण गुणवत्ता और पारदर्शिता के साथ पूरा करेगी, ताकि इसका प्रत्यक्ष लाभ पीवीटीजी आबादी को शीघ्र मिल सके। इन सड़कों और पुलों के निर्माण से न केवल इन दुर्गम क्षेत्रों में जीवन सुगम होगा, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा, बाजार और शासन से जुड़ाव भी सुनिश्चित हो सकेगा।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह पहल माननीय प्रधानमंत्री जी के 'विकसित भारत ञ्च2047' के संकल्प की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जो यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी नागरिक, चाहे वह देश के कितने ही सुदूर या वंचित क्षेत्र में क्यों न हो, विकास की मुख्यधारा से वंचित न रहे। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को निर्देशित किया है कि वे स्वीकृत पुलों और सड़कों का निर्माण कार्य प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र प्रारंभ करें और सभी कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग, स्थानीय जनसुनवाई, एवं समयबद्ध प्रगति रिपोर्टिंग सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के पीवीटीजी समुदायों के जीवन में ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिलेगा।

कृषि के विद्यार्थियों ने सीखा खेती में ड्रोन का उपयोग

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर में कृषि में ड्रोन के उपयोग विषय पर कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम 31 जुलाई से 06 अगस्त, 2025 तक कृषि महाविद्यालय, रायपुर में आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम विश्वविद्यालय के प्लेसमेंट सेल, अखिल भारतीय समन्वित खरपतवार प्रबंधन परियोजना एवं न्यू स्काई-कलश वेंचर्स के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के स्नातक, स्नातकोत्तर एवं पीएचडी के 70 प्रतिभागियों ने भाग लिया। तीन दिन प्रतिभागियों को कलश वेंचर्स के ट्रेनर्स ने ड्रोन के हार्डवेयर, कृषि में उपयोगिता और इसमें व्यवसाय खड़ा करने की संभावनाओं पर प्रकाश डाला। कौशल प्रशिक्षण के चौथे, पांचवे एवं छठे दिन प्रतिभागियों ने ट्रेनर्स के मार्गदर्शन में ड्रोन उड़ाना सीखा। प्रशिक्षण के अंतिम दिन प्रतिभागियों का लिखित मूल्यांकन किया गया।

कार्यक्रम के समापन में डॉ. गिरीश चंदेल, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र वितरित किये गए। डॉ. चंदेल ने आधुनिक कृषि में ड्रोन के प्रभावी उपयोग और इसके माध्यम से

फसलों की निगरानी पर अपने विचार व्यक्त किये। उन्होंने प्रतिभागियों से प्रशिक्षण कार्यक्रम का फीडबैक भी लिया। डॉ. चंदेल ने कहा कि अब ये सारे प्रतिभागी हमारे अन्य विद्यार्थियों को भी इस क्षेत्र में व्यवसाय की संभावनाएं तलाशने हेतु जागरूक करेंगे। कार्यक्रम के समापन अवसर पर डॉ. संजय शर्मा अधिष्ठाता छात्र कल्याण, डॉ. आरती गुहे अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय रायपुर, डॉ. विनय पांडेय अधिष्ठाता कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय रायपुर, डॉ. एस.एस. टूटेजा निदेशक विस्तार सेवाएं, महाविद्यालय के विभिन्न विभागाध्यक्ष, प्लेसमेंट सेल के अधिकारी एवं छात्र छात्राएं उपस्थित थे। संपूर्ण प्रशिक्षण ट्रेनर सुभाशीष पटनायक, द्वारा दिया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉ. नीतीश तिवारी, डॉ. रामा मोहन सावू एवं डॉ. शुभा बैनर्जी ने किया।

उत्तर बस्तर के पीडीएस गोदामों का निगम अध्यक्ष ने किया निरीक्षण

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव ने उत्तर बस्तर के जिला कांकेर एवं कोंडागांव स्थित खाद्यान्न गोदाम चारामा एवं केशकाल का औचक निरीक्षण किया। अध्यक्ष श्रीवास्तव ने निगम की गठित राज्य स्तरीय दल के साथ चारामा, केशकाल स्थित वेयर हाउस गोदाम पहुंचकर पीडीएस के वितरण के लिए निगम द्वारा उपार्जित चावल एवं संग्रहित नमक, गुड़, शक्कर का अवलोकन किया। अध्यक्ष श्रीवास्तव ने इस दौरान नागरिक आपूर्ति निगम कांकेर एवं कोंडागांव के जिला प्रबंधक, गोदाम प्रभारी, वेयर हाउस प्रबंधक एवं स्टाफ की उपस्थिति में स्टेक से चावल का सेम्पल निकलवा कर वरिष्ठ तकनीकी कर्मचारी से गुणवत्ता का परीक्षण कराया, जो मानक स्तर का पाया गया। गोदाम में उपलब्ध अन्य राशन साम्रागी के बोरो का भी वजन की जांच कराई गई।

निरीक्षण के दौरान श्रीवास्तव ने गोदाम एवं कार्यालय में साफ-सफाई का अभाव, गोदाम के प्लेटफार्म में टूट-फूट, छत में कुछ स्थानों में छेद होने से पानी टपकने की स्थिति को देखकर गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने वेयर हॉउस प्रभारी को कार्यालय एवं गोदाम की साफ-सफाई, प्लेटफार्म एवं छत मरम्मत एवं गोदाम के रंग-रोगन कराने के निर्देश दिए।

गगन का घर सौर ऊर्जा से हुआ रौशन : बिजली बिल से मिली मुक्ति

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ ऊर्जा स्वावलंबन की दिशा में सरकार की प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना आम लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो रही है। इस योजना से नागरिकों को न केवल बिजली बिल से राहत मिल रही है, बल्कि वे अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन कर आय का साधन भी बना रहे हैं। राजनांदगांव शहर के कमला कॉलेज रोड निवासी गगन गुप्ता ने इस योजना का लाभ लेते हुए अपने घर की छत पर 10 किलोवाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। उन्होंने बताया कि इस संयंत्र की कुल लागत लगभग 5 लाख रुपये आई, जिसमें शासन द्वारा 78 हजार रूपए की अनुदान सहायता प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि पूर्व में उन्हें प्रतिमाह 10 हजार से 15 हजार रूपए तक का बिजली बिल चुकाना पड़ता था, परंतु सोलर संयंत्र स्थापना के बाद अब उनका बिजली बिल शून्य हो गया है। साथ ही, अतिरिक्त बिजली ग्रिड में जमा होकर भविष्य में आय का स्रोत भी बन रही है। गगन ने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के अंतर्गत बैंक से ऋण प्राप्त करना भी सरल है। उन्होंने इस योजना को अत्यंत उपयोगी बताते हुए अधिक से अधिक लोगों से इसका लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह योजना उपभोक्ताओं को ऊर्जा उत्पादक बनने का अवसर देती है, जिससे न केवल आर्थिक लाभ होता है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान सुनिश्चित होता है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री सूर्यघर-मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत नागरिकों को अपनी छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर विद्युत उत्पादन करने का अवसर मिल रहा है। संयंत्र से उत्पादित अतिरिक्त बिजली नेट मीटरिंग प्रणाली के माध्यम से ग्रिड में भेजी जाती है, जिससे उपभोक्ता को बिल में छूट के साथ-साथ अतिरिक्त आय भी होती है। योजना के तहत 3 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता के संयंत्र पर अधिकतम एक लाख 8 हजार रूपए तक की सब्सिडी का प्रावधान है।

हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ी ग्राम बघमरा की महिलाओं की सशक्त पहल

अब तक 6,000 से अधिक तिरंगे तैयार, आत्मनिर्भरता और देशभक्ति की मिसाल बनीं महिलाएं

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा अभियान पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। बालोद जिले के ग्राम बघमरा में यह अभियान महिला सशक्तिकरण एवं आत्मनिर्भरता की प्रेरणादायक मिसाल बन गया है। यहाँ की चार स्व-सहायता समूहों की महिलाएं तिरंगा झण्डा बनाने में जोर-शोर से जुटी हैं। अब तक इन महिलाओं द्वारा 6,000 से अधिक तिरंगे झंडे तैयार किए जा चुके हैं, जिससे उन्हें लगभग दो लाख रुपये की आय प्राप्त हुई है।

यह पहल न केवल स्थानीय महिलाओं के लिए आजीविका का नया माध्यम बनी है, बल्कि राष्ट्रभक्ति और गौरव का भाव भी उनमें सशक्त रूप से जागृत कर रही है। इन

समूहों द्वारा तैयार किए गए तिरंगे स्थानीय बाजारों, दुकानों और शासकीय कार्यालयों में स्थापित स्टॉल्स के माध्यम से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जय कपिलेश्वर समूह की श्रीमती तिजन बाई ने बताया कि, हमारी सिलाई मशीनें दिन-रात चल रही हैं। हर झंडे में हमारा प्रेम और देशभक्ति की भावना समाहित होती है। यह कार्य हमें आत्मनिर्भर बना रहा है और देशसेवा का गौरव भी प्रदान कर रहा है।

सहेली समूह की श्रीमती देवकी विश्वकर्मा ने कहा कि पहले हम छोटे-मोटे कार्यों पर निर्भर थे, लेकिन इस अभियान ने हमें एक नई पहचान दी है। तिरंगा बनाना केवल कार्य नहीं, बल्कि देश के लिए कुछ कर गुजरने का जुनून है। नवज्योति समूह की श्रीमती सरोजनी साहू ने गर्व के साथ बताया कि हमारी मेहनत से तैयार तिरंगे जब गाँव और जिले के घरों में लहराते हैं, तो आत्मगौरव की अनुभूति होती है। हमारा प्रयास है कि हर घर में तिरंगा फहराया जाए और हमारा गाँव इस अभियान में अग्रणी बने। इन समूहों द्वारा बनाए जा रहे तिरंगों की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। सिलाई मशीनों के माध्यम से महिलाएं राष्ट्रध्वज के तीन रंग केसरी, सफेद और हरे को संयोजित कर सटीकता के साथ तैयार कर रही हैं।

कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने जिलेवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की है। उन्होंने कहा कि महिला समूहों के द्वारा मेहनत से बनाए गए तिरंगे आपके घरों की शान बनेंगे। 15 अगस्त को अपने घर पर तिरंगा फहराकर देशभक्ति का पर्व मनाएं। बिहान के सहायक परियोजना अधिकारी ने बताया कि जिले में अब तक 13 स्वयं सहायता समूहों द्वारा 8,000 से अधिक तिरंगे झंडे तैयार कर विक्रय किए जा चुके हैं तथा 5,000 तिरंगों का अतिरिक्त ऑर्डर प्राप्त हुआ है। हर घर तिरंगा अभियान ने ग्राम बघमरा की महिलाओं के लिए आजीविका का मजबूत साधन बनकर उन्हें आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ाया है।

हर घर तिरंगा अभियान के तहत बिहान दीदियों ने लगाया बिलासपुर में स्वदेशी उत्पादों का तिरंगा बाजार

रायपुर। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत जिला पंचायत परिसर, बिलासपुर में बिहान स्व-सहायता समूह की दीदियों द्वारा तीन दिवसीय प्रदर्शनी सह विक्रय केंद्र का आयोजन किया गया है। इस विशेष तिरंगा बाजार में दीदियों द्वारा तैयार किए गए स्वदेशी उत्पादों की बिक्री की जा रही है, जिसमें तिरंगा, राखियां, पूजन सामग्री, तिरंगा जैकेट, अगरबत्ती, सजावटी सामान, अचार, पापड़ जैसी घरेलू वस्तुएं शामिल हैं। इस पंडाल का उद्घाटन जिला पंचायत अध्यक्ष बिलासपुर और कलेक्टर ने किया। दोनों अधिकारियों ने स्टॉल पहुंचकर राखियां और पूजन सामग्री की खरीदारी कर दीदियों का उत्साहवर्धन किया।

खास खबर

हत्या का आरोपी बेटा गिरफ्तार, जशपुर में टांगी मारकर बेरहमी से किया कत्ल

जशपुर। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में कलयुगी बेटे ने अपनी की मां की बेरहमी से हत्या कर दी। घर की परछी पर चटाई बिछाकर सो रही मां से पहले विवाद हुआ और इसके बाद उसने टांगी से ताबड़तोड़ वार किए। घटना की सूचना के बाद पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। घटना बुधवार दोपहर की है। मामला जिले के तुमला थाना क्षेत्र का है।

मिली जानकारी के अनुसार 6 अगस्त को प्रार्थी सुबरन राम ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई। उसने अपनी शिकायत बताया कि उसकी बहन दशमती बाई व उसका भांजा कमल राम ग्राम गौरीघाट में रहते हैं। 6 अगस्त 25 को वह उनके घर पर गया था। दोपहर को सभी खाना खाकर आराम कर रहे थे। उसकी बहन दशमती बाई, उसके घर की परछी में चटाई बिछा कर लेटी हुई थी। कुछ देर बाद चीखने चिल्लाने की आवाज आई तो सुबरन बाहर निकला। देखा कि उसका भांजा कमल राम अपनी मां पर टांगी से वार कर रहा है। जब तक वह पहुंचा दशमती बाई की मौत हो चुकी थी। वहीं घटना के बाद कमल राम वहां से भाग गया।

रिपोर्ट पर पुलिस के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी कमल राम उम्र 25 वर्ष के खिलाफ थाना तुमला में हत्या के लिए बीएनएस की धारा 103(1) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच विवेचना में लिया गया। घटना स्थल का निरीक्षण कर शव को पोस्ट मार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। इसके बाद पुलिस ने त्वरित एक्शन लेते हुए आरोपी को चंद घंटों के भीतर ही हिरासत में ले लिया। आरोपी ने बताया कि उसका मां से विवाद होता रहता था इसलिए उसने उसकी हत्या कर दी। आरोपी कमल राम के द्वारा अपराध स्वीकार करने व प्रयास अपराध सबूत पाए जाने पर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।

बिना हेलमेट गए तो अब नहीं मिलेगी शराब

छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में कलेक्टर का फरमान, पेट्रोल के भी पड़ेंगे लाले

श्रीकंचनपथ न्यूज

बालोद। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में प्रशासन द्वारा सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कठोर निर्णय लिया है। कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा एवं पुलिस अधीक्षक योगेश पटेल ने गुरुवार को संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में जिले के पेट्रोल पंप संचालकों एवं दोपहिया वाहन विक्रेताओं की बैठक लेकर इस संबंध में आवश्यक दिशानिर्देश दिए हैं। अब जिले के किसी भी पेट्रोल पंप में बिना हेलमेट के गए तो पेट्रोल नहीं मिलेगा। यही नहीं जिले की शराब दुकानों में भी दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट देखकर ही शराब भी दी जाएगी।

कलेक्टर दिव्या मिश्रा ने कहा कि प्रत्येक नागरिकों की जीवन की सुरक्षा करना हम सभी की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। कलेक्टर ने कहा कि इस अभियान को सफल बनाने में समाज के सभी वर्गों की सहभागिता एवं सामाजिक भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। कलेक्टर ने इस अभियान को सफल बनाने में पेट्रोल पंप संचालकों एवं दोपहिया वाहन विक्रेताओं को महत्वपूर्ण कड़ी मानते हुए, उन्हें जनहित के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने की अपील की है। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुनील चंद्रवंशी, अपर कलेक्टर अजय किशोर लकरा, जिला आबकारी अधिकारी योगेश द्विवेदी सहित पुलिस एवं अन्य अधिकारियों के अलावा जिले के पेट्रोल पंप संचालक एवं दोपहिया वाहन विक्रेता उपस्थित थे।

दोपहिया वाहन चालक हेलमेट को आदत में करें शामिल

कलेक्टर दिव्या मिश्रा ने कहा कि दोपहिया वाहन चालक हेलमेट का उपयोग करना सुनिश्चित कर दें, तो सड़क दुर्घटना में मृत्यु की दर में बहुत कुछ कमी आ सकती है। जिसे देखते हुए जिला एवं पुलिस प्रशासन के द्वारा सभी दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट का अनिवार्य रूप से उपयोग कराने हेतु सख्त कदम उठाया जा रहा है। इसके अलावा कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने जिले के दोपहिया वाहन विक्रेताओं को उनके दुकानों से दोपहिया वाहन खरीदने वाले ग्राहकों को दोपहिया वाहन के साथ साथ अनिवार्य रूप से हेलमेट भी प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को परिवहन विभाग से समन्वय स्थापित कर पेट्रोल पंप के समीप आईएसआई मार्क वाले हेलमेट दुकान प्रारंभ करने के निर्देश भी दिए। श्रीमती मिश्रा ने जिला परिवहन अधिकारी को इस संबंध में शीघ्र जरूरी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

शराब की दुकानों में भी हेलमेट जरूरी

बैठक में सर्वसम्मति से जिले के शासकीय शराब दुकानों में दोपहिया वाहन के माध्यम से बिना हेलमेट पहने शराब खरीदी हेतु आने वाले लोगों को भी शराब की बिक्री नहीं करने का निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि जान है तो जहान है इसलिए शराब दुकानों में भी दोपहिया वाहन में बिना हेलमेट पहने आने वाले लोगों को शराब की बिक्री प्रतिबंधित करना अत्यंत आवश्यक है। कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने जिला आबकारी अधिकारी को इस संबंध में आदेश जारी कर इसका शतप्रतिशत पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने हेतु नियमित रूप से पुलिस बल के द्वारा पेट्रोलिंग कराने तथा निर्धारित स्थलों पर पुलिस जवानों की भी ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए। मिश्रा ने जिला आबकारी अधिकारी को परिवहन विभाग से समन्वय स्थापित कर शराब दुकानों के समीप आईएसआई मार्क वाले हेलमेट दुकान प्रारंभ करने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने बिना हेलमेट पहनकर पेट्रोल पंप में पेट्रोल खरीदने के लिए आने वाले बच्चों को भी विशेष समझाईश देने को कहा।

सरकारी विभागों के अधिकारी कर्मचारियों के लिए भी हेलमेट अनिवार्य

कलेक्टर मिश्रा ने संयुक्त जिला कार्यालय परिसर स्थित कलेक्टोरेट एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय तथा जिला पंचायत एवं रक्षित आरक्षी केन्द्र में दोपहिया वाहन से कार्यालय आने वाले सभी अधिकारी, कर्मचारियों के लिए भी हेलमेट का उपयोग सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। इस कार्य को सुनिश्चित कराने हेतु उन्होंने पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्धारित स्थानों पर पुलिस के जवानों की तैनातगी भी कराने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने दोपहिया वाहन के माध्यम से बिना हेलमेट पहने कार्यालय आने वाले तथा नियमों का अवहेलना करने वाले अधिकारी कर्मचारियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन के माध्यम से शासकीय कार्यालयों में आने वाले आम नागरिकों के विरूद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने आम नागरिकों को दोपहिया वाहन चलाते वक्त हेलमेट की महत्ता एवं उपयोगिता की जानकारी देने हेतु जनजागरूकता अभियान चलाकर इसका समुचित प्रचार प्रसार भी कराने के निर्देश दिए।

बैनर पोस्टर के जरिए करें लोगों को जागरुक

इसके अंतर्गत उन्होंने पेट्रोल पंपों में बैनर पोस्टर आदि के माध्यम से इसकी जानकारी देने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कोटवारों के माध्यम से मुनादि कराकर आम नागरिकों को इसके संबंध में जानकारी प्रदान कराने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने सभी पेट्रोल पंपो में सीसीटीवी कैमरा की उपलब्धता सुनिश्चित कराकर, इसे पूरे समय क्रियाशील रखने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों एवं दोपहिया वाहन विक्रेताओं को आज की बैठक में दिए गए निर्देशों का शतप्रतिशत पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला एवं पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा नियमित रूप से सभी पेट्रोल पंपों का निरीक्षण किया जाएगा। प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं होने पर संबंधित पेट्रोल पंप संचालकों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की भी चेतावनी दी।

सभी वर्गों की सहभागिता एवं जनभागीदारी से थमेंगे हादसे

बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री योगेश पटेल ने कहा कि सड़क दुर्घटना आम नागरिकों के जीवन से जुड़े अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। समाज के सभी वर्गों की सहभागिता एवं जनभागीदारी से ही सड़क दुर्घटना के रोकथाम सुनिश्चित की जा सकती है। उन्होंने जिले के पेट्रोल पंप संचालकों से आग्रह किया कि विषय की गंभीरता को देखते हुए किसी भी स्थिति में दोपहिया वाहनों में बिना हेलमेट पहनकर आने वाले लोगों को किसी भी स्थिति में पेट्रोल न दें। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा उठाया गया यह कदम आम नागरिकों के उपर सख्ती बरतना बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन सड़क दुर्घटना के दौरान होने वाल जनहानि को रोकने के लिए उन्हें हेलमेट के उपयोग के लिए प्रेरित करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने पेट्रोल पंप संचालकों एवं दोपहिया वाहन विक्रेताओं को इस अभियान का महत्वपूर्ण कड़ी मानते हुए जनहित में प्रशासन का हर संभव मदद करने की अपील भी की। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि तेजी से बढ़ रहे सड़क दुर्घटना की रोकथाम सुनिश्चित करने तथा इस दौरान होने वाली जनहानि को रोकने हेतु उठाए गए इस महत्वपूर्ण कार्य में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करना समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों की नैतिक जिम्मेदारी भी है। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुनील चंद्रवंशी एवं अपर कलेक्टर श्री अजय किशोर लकरा ने भी जिले में सड़क दुर्घटना की रोकथाम सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक सुझाव देते हुए जिले के पेट्रोल पंप संचालकों एवं दोपहिया वाहन विक्रेताओं से इस महत्वपूर्ण अभियान को सफल बनाने हेतु प्रशासन का हर संभव सहयोग करने की अपील की। बैठक में उपस्थित पेट्रोल पंप संचालकों एवं दोपहिया वाहन विक्रेताओं से भी सुझाव लिया गया।

बीजापुर में तीन लाख का इनामी जनमिलिशिया कमांडर गिरफ्तार, लंबे समय से था नक्सल संगठन में सक्रिय

श्रीकंचनपथ न्यूज

बीजापुर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षाबलों को एक बड़ी सफलता मिली है। डीआरजी बीजापुर और सीआरपीएफ 85वीं बटालियन की संयुक्त कार्रवाई में 3 लाख रुपये के इनामी जनमिलिशिया कमांडर शंकर कुरसम को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी पेद्दापाल और हिरमागुंडा के मध्य जंगल से की गई। शंकर कुरसम 36 वर्ष निवासी इसुलनार, थाना बीजापुर, लंबे समय से नक्सल संगठन में सक्रिय था और कई गंभीर घटनाओं में शामिल रहा है।

गिरफ्तार नक्सली के खिलाफ बीजापुर थाना क्षेत्र में प्रमुख रूप से 23 दिसंबर 2023 ग्राम मनकेली में छोटू कुरसम की हत्या, 25 दिसंबर 2023 गोरना-मनकेली मार्ग पर आईईडी ब्लास्ट, जिसमें डीआरजी का एक जवान घायल हुआ, 24 मार्च 2024 अटल आवास परिसर में डीआरजी जवान पर फायरिंग, 09 अप्रैल 2025 सिंगार बहार नाला के पास आईईडी विस्फोट, जिसमें सीआरपीएफ 196 बटालियन का एक जवान गंभीर रूप से घायल हुआ और बाद में शहीद हो गया। इसके अतिरिक्त, 29 जुलाई 2025 को पेद्दाकोरमा-बोड़ला पुसनार जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में भी शंकर कुरसम की संलिप्तता पाई गई है। शंकर कुरसम की गिरफ्तारी पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 3 लाख और पुलिस अधीक्षक बीजापुर द्वारा 10 हजार का इनाम घोषित था। गिरफ्तार नक्सली को थाना कोतवाली बीजापुर में वैधानिक कार्यवाही के बाद न्यायिक रिमांड पर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।

नौकरी के नाम पर 6 जिलों में ठगी, शातिर बदमाश दुर्ग पुलिस के हत्थे चढ़ा, 30 लाख से ज्यादा का है मामला

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। स्मृति चौकी पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले शातिर बदमाश को महसमुंद से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने 6 जिलों में बेरोजगारों को झांसे में लेकर ठगी है। 30 लाख रुपए से भी ज्यादा की ठगी के मामले में अपराध दर्ज है।

प्रार्थी ढालसिंह वर्मा ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि 6 मार्च 2020 को आरोपी साबास खान के साथ प्रार्थी का परिचय हुआ था। उसने अपने आपको मंत्रालय में बाबू होना बताकर प्रार्थी एवं उनके साथीयों को अपने विश्वास में लेकर मंत्रालय रायपुर एवं पोस्ट ऑफिस में सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर नगद एवं बैंक के माध्यम से 30 लाख 94000 हजार रुपए ले लिए। रिपोर्ट पर पुलिस चौकी स्मृति नगर में अपराध क्रमांक 910/2025 धारा 420 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए तत्काल आरोपी साबास खान की पता तलाश हेतु पुलिस टीम महासमुंद भेजा गया था, जो स्थानीय पुलिस की मदद से आरोपी साबास खान के घर में दबिश देकर पकड़ा गया। पूछताछ पर आरोपी के द्वारा अपराध घटित करना स्वीकार करने उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। आरोपी के खिलाफथाना दर्री जिला कोरबा, थाना गोलबाजार रायपुर, थाना कोतवाली जिला महासमुंद, थाना बंसतपुर जिला राजनांदगावं व थाना छुरा जिला गरियाबंद में भी ठगी के मामले दर्ज है। इस पूरी कार्रवाई में उप निरीक्षक गुरूविन्दर सिंग संधु, प्रधान आरक्षक अनुप साहू, आरक्षक अनिकेत चंद्राकर, कौशलेन्द्र सिंह, कमल नारायण सराहनीय रही।

जंगली सुअर को मारने लगाया करंट

रायगढ़। जिले के घने जंगल में जानवरों के शिकार किए जाने का मामला सामने आया है। जहां बंगुरसिया पश्चिम सर्किल क्षेत्र में शिकारियों ने 5 किमी तक लंबा करंट का तार लगा दिया। सूचना मिलते ही वन विभाग ने गुरुवार (7 अगस्त) को बिजली सप्लाई बंद कर तार हटाया। जानकारी के मुताबिक, शिकारियों ने जंगली सुअर मारने के लिए पड़ीगांव से कक्ष क्रमांक 914 की ओर खेतों और जंगल में तार बिछाया था। ये इलाका हाथी प्रभावित क्षेत्र है। साल भर यहां हाथियों की मौजूदगी रहती है। ऐसे में करंट से हाथियों के मारे जाने का भी डर था। वहीं, ग्रामीणों को भी खतरा था। इस तरह खेतों से करंट तार गुजरने से इस क्षेत्र में आने-जाने वाले किसी भी ग्रामीण की जान जा सकती थी। वन अमला ने करंट के लिए लगाए गए जीआई तार को जब्त करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

दुर्ग में लिफ्ट देने के बहाने राहगीर से लूट

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। दुर्ग के पुलगांव थाना क्षेत्र में लिफ्ट देने के बहाने राहगीर से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने पहले लिफ्ट दिया और सुनसान जगह पर ले जाकर मारपीट की और उसके बाद उसके पास रखे 61 हजार रुपए कैश लूट कर फरार हो गए। घटना के संबंध में राहगीर ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। इस मामले में पुलगांव पुलिस ने बीएनएस की धारा 309(6) के तहत अपराध दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

मिली जानकारी के अनुसार धमधा निवासी विश्वजीत मन्ना मछली बीज का व्यापार करता है। 6 अगस्त की दोपहर 12 बजे मछली बीज को लेकर आईचर वाहन में धमधा से धमतरी गया था। धमतरी में मछली बीज को बेचकर वहां से 61,530 रुपए नगदी कैश लेकर वापस दुर्ग बस स्टेशन में रात्रि करीबन 9.40 बजे पहुंचा। दुर्ग बस स्टेशन से आटो करके ग्रीन चौक पहुंचा। ग्रीन चौक में गाड़ी का इंतजार कर रहा था लेकिन धमधा जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं मिल रही थी। इस दौरान ग्रीन चौक एक बाईक में दो लडके आये और पूछा कि कहां जाना है। तो मैं बोला कि मुझे धमधा जाना है। दोनों बोले हम खैरागढ जा रहे हैं आपको धमधा में छोड देंगे।

विश्वजीत को उन दोनों ने अपनी बाइक के बीच में बैठाया और जब हम सांई कालोनी के सामने, खण्डेलवाल राईस मिल के पास चिखली लगभग 10.15 बजे पहुंचे तो दोनों ने गाडी रोका और अंदर के तरफखाली प्लाट में ले जाकर मुझे जान से मारने की धमकी दी। दोनों ने विश्वजीत से मारपीट कर उसके जेब में रखी नगदी 61 हजार 530 रुपए लूटकर फरार हो गए। इसके बाद पास में एक कार वाले से फोन लेकर उसने अपने घर पर सूचना दी। घरवालों की सलाह पर थाने शिकायत दर्ज कराने पहुंचा। प्रार्थी ने पुलिस को बताया कि बाइक चलाने वाला काला कलर का शर्ट, दिखने में पतला, रंग गोरा, लगभग 18 से 20 वर्ष का लग रहा था। पीछे बैठने वाला व्यक्ति सफेद कलर का शर्ट पहन हुआ था और रंग गोरा, शरीर दुबला पतला, उम्र लगभग 18 से 20 वर्ष का लग रहा था। दोनो छत्तीसगढी में बात कर रहे थे।

कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड, राजेन्द्र पार्क चौक दुर्ग (छ.ग.)

दूरभाष क्र. 0788-2323633 E-mail:eedurg-phe-cg@nic.in

नि.सू.क्र. 08/तशा/(निविदा)/का.अ./लो.स्वा.यां.खंड/2025 दुर्ग, दिनांक 04.08.2025

// मैन्युअल पद्धति निविदा सूचना //

छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल की ओर से एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत श्रेणी ''डी'' एवं उच्च में पंजीकृत ठेकेदारों से ''प्रपत्र ए'' में प्रतिशत दर पर दुर्ग जिले के हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी में 150 मि.मी. व्यास के 120 मीटर गहरे नलकूप खनन कर, 2 एच.पी. सबमर्सिबल पंप प्रदाय सहित स्थापना कार्य हेतु मैनुअल निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 20.08.2025 शाम 5.30 बजे है।

नि.सू.क्र./दिनांक	समूह क्र.	नलकूप की संख्या	स्थान का नाम	अनुमानित लागत (रू. लाख में)
08/दि. 04.08.2025	01	03 नग	हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी दुर्ग	4.68

यह निविदा सूचना मूल निविदा का एक अंग है। विस्तृत निविदा एवं पूर्ण जानकारी इस कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखी जा सकती है।

कार्यपालन अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड
दुर्ग (छ.ग.)

जी-252602655/3

CHANGE IN PARTNERSHIP FIRM

This Public Notice is to inform all concerned parties that the Partnership Deed dated 20-11-23, originally executed between Vijay Kumar Swami, Monika Swami, Vibhav Parman, and Sourabh Kumar Dewangan has been amended. Monika Swami has retired and the profit-sharing ratio has been modified.

The above changes to the Partnership Deed shall be effective from 11-07-2025. All other terms and conditions of the Original Deed, not specifically modified herein, shall remain in full force and effect.

Signed and agreed to by all partners:þ

11-07-2025

Vijay Kumar Swami
Vibhav Parmar
Sourabh Kumar Dewangan

समक्षः-श्रीमान पब्लिक नोटरी महोदय दुर्ग, जिला दुर्ग (छ.ग.)

शपथपत्र (नाम परिवर्तन)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं जितेन्द्र सिंह (Jitendra singh) पिता श्री दलवीर सिंह (Dalveer singh) उम्र 35 वर्ष, निवासी-जुनियर एम.आई.जी.-969, हाउसिंग बोर्ड भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) यह शपथपूर्वक पेश करता हूं कि मैने अपना यह पुराना नाम Jitendrasingh, Jitendra को त्याग नया नाम जितेन्द्र सिंह Jitendra singh रख लिया हूं अतः आज से मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय/वित्तीय संस्थान व अन्य दस्तावेजों में मेरा नया नाम जितेन्द्र सिंह Jitendra singh दर्ज किया जावे एवं नया नाम से ही जाना पहचाना व पुकारा जावें।

जितेन्द्र सिंह (Jitendra singh) पिता श्री दलवीर सिंह (Dalveer singh) उम्र 35 वर्ष, निवासी-जुनियर एम.आई.जी.-969, हाउसिंग बोर्ड भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.)

Shop-47, 'A' Market, Sec-6, Bhilai Nagar, Distt., Durg (C.G.)

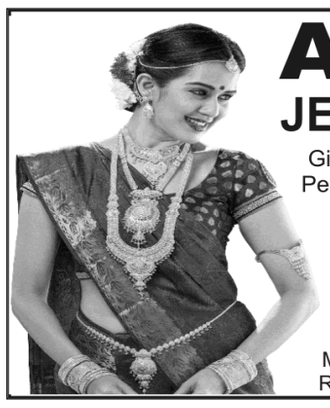
Ashok
JEWELLERY
Gifts ● Toys ● Cosmetics
Perfumes ● Sia Jewellery
Beside Parakh Jewellers,
Akash Ganga,
Supela, Bhilai
Hello: 0788-4052727
Mukesh Jain 9009959111
Rishabh Jain 8103831329

राकेश ट्रेडर्स
राकेश ट्रेडर्स जो चर्च के पास था वह आगे चला गया है पिछले दस वर्षो से
Dealers
Marbles, Grinight, Black Stone, Nano & Double Charge Verified Tiles Digital Wall & Floor Tiles Cement Coloru etc.

रायपुर रेट पर माल उपलब्ध
Rakesh Sahu
9302443750, 9907127357
Krishna Talkies Road, Beside Swami Aatmanad School, Risali, Bhilai - 490006

भिलाई मसाला उद्योग

शुद्ध कुटे हुए मसाले,पापड़, अचार, बड़ी, जड़ी-बूटी, जचकी का सामान इत्यादि
128, ए- मार्केट, सेक्टर-6, भिलाई, फोन. 2284508, मो. 9826137766

अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का बजट 50 करोड़ से बढ़ाकर 75 करोड़ पांच युवाओं को हर साल पायलट बनाने दी जाएगी आर्थिक सहायता

मुख्यमंत्री साय ने कहा : अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण मद से स्वीकृत कार्यों को गंभीरता से लेकर पूरी गुणवत्ता के साथ समय सीमा में पूर्ण कराएं कलेक्टर्स

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में गुरुवार को जांजगीर-चांपा जिले के जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की बैठक में प्राधिकरण के बजट को 50 करोड़ से बढ़ाकर 75 करोड़ रुपये करने की स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्रीसाय ने निर्देश दिए कि प्राधिकरण मद से स्वीकृत कार्यों को सभी कलेक्टर्स गंभीरता से लें और उन्हें उच्च गुणवत्ता के साथ निर्धारित समयसीमा में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अब प्राधिकरण की बैठक हर वर्ष समय पर आयोजित होगी और कार्यों की गहन समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि संविधान की मंशा के अनुरूप अनुसूचित जाति समुदाय के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक उत्थान के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रदत्त संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करते हुए हम बाबा गुरु घासीदास जी के 'मनखे-मनखे एक समान' के संदेश को आत्मसात कर समाज में सम्मान और समानता की भावना को सशक्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुँचे, यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि जांजगीर-चांपा जिले को इस बैठक के लिए विशेष रूप से इसलिए चुना गया क्योंकि यह अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य अपनी स्थापना के 25वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है, और अब समय आ गया है कि हम विकास की दिशा में नए कीर्तिमान स्थापित करें। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की संकल्पना के अनुरूप राज्य में विकास के कार्य हुए हैं। अनुसूचित जाति समाज के समुचित विकास के लिए प्राधिकरण एक सशक्त माध्यम है, जिसके माध्यम से सरकार ठोस प्रयास कर रही है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने गिरौधपुरी धाम के विकास के लिए 2 करोड़ रुपये, अजा वर्ग के विद्यार्थियों हेतु कोचिंग व्यवस्था के लिए 50 लाख रुपये, प्रत्येक वर्ष अनुसूचित जाति वर्ग के 5 युवाओं को पायलट प्रशिक्षण हेतु सहायता, तथा जोड़ा जैतखंभ के निर्माण में सीमेंट के साथ-साथ लकड़ी के उपयोग हेतु राशि स्वीकृत करने की घोषणा की। साथ ही, दिल्ली में संचालित ट्राइबल यूथ हॉस्टल में सीट संख्या बढ़ाकर 200 करने की जानकारी दी और विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु इसका लाभ लेने हेतु प्रेरित किया। उन्होंने आगामी समय में सभी जिला मुख्यालयों में 'नालंदा परिसर' के निर्माण की भी बात कही।

मुख्यमंत्री श्री साय ने बैठक के दौरान प्राधिकरण मद से स्वीकृत कार्यों के वर्षों से लंबित रहने पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि भले ही प्राधिकरण के कार्यों की राशि कम हो, लेकिन उनका सामाजिक महत्व अत्यंत बड़ा है। इन कार्यों का समय पर पूर्ण न होना चिंता का विषय है। बैठक को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में अनुसूचित जाति समाज के उत्थान के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री की सोच समाज के वंचित वर्ग को मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में स्पष्ट है। उन्होंने सभी लंबित कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए और सभी समाज को साथ लेकर छत्तीसगढ़ के समग्र विकास का संकल्प दोहराया।

अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष गुरु खुशवंत साहेब ने मुख्यमंत्रीसाय के नेतृत्व में समाज के विकास के लिए किए जा रहे कार्यों हेतु आभार प्रकट किया। उन्होंने गिरौधपुरी धाम में रोपवे निर्माण, मेला आयोजन के दौरान बुनियादी सुविधाओं के विस्तार, जोक नदी के पास स्नान हेतु आवश्यक व्यवस्था, ठहरने की सुविधा, जोड़ा जैतखंभ में लकड़ी के उपयोग, बाराडेरा धाम में ऐतिहासिक तालाब का संरक्षण और सौंदर्यीकरण, विद्यार्थियों के लिए स्मार्ट क्लास की व्यवस्था जैसी मांगें बैठक में रखीं। उन्होंने बजट वृद्धि और मांगों की स्वीकृति के लिए भी आभार व्यक्त किया।

बैठक में प्राधिकरण के स्वरूप, कार्यक्षेत्र, अनुमोदित कार्यों की समीक्षा, बजट प्रावधानों की जानकारी, एवं वित्तीय वर्ष 2020 से 2025 तक स्वीकृत कार्यों की प्रगति सहित नागरिक सुविधाओं, सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियों, और शैक्षणिक सुविधा विस्तार जैसे विषयों पर गहन चर्चा की गई। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों एवं प्राधिकरण सदस्यों के प्रस्तावों के आधार पर 49 करोड़ रुपये से अधिक की राशि के विकास एवं हितग्राही मूलक कार्यों का अनुमोदन किया गया।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव, उपाध्यक्ष गुरु खुशवंत साहेब, मंत्री दयाल दास बघेल, लखन लाल देवांगन, लक्ष्मी राजवाड़े, टंकराम वर्मा, सांसद कमलेश जांगड़े, विधायक पुन्नूलाल मोहले, डोमनलाल कोर्सेवाड़ा, दिलीप लहरिया, शेषराज हरवंश, उतरी गणपत जांगड़े, श्रीमती कविता प्राण लहरे, हर्षिता स्वामी बघेल सहित रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग के आयुक्त, आईजी, एवं 17 जिलों के कलेक्टर उपस्थित थे।

उल्लेखनीय है कि अनुसूचित जाति प्राधिकरण का कार्यक्षेत्र संपूर्ण राज्य है जिसमें प्रदेश के 17 अनुसूचित जाति बाहुल्य जिले- जांजगीर-चांपा, सक्ती, बिलासपुर, मुंगेली, रायपुर, बलौदाबाजार-भाटापारा, गरियाबंद, रायगढ़, सारंगढ़-बिलाईगढ़, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, महासमुंद, राजनांदगांव, खैरागढ़ सहित अन्य वे जिले भी शामिल हैं, जिनमें अनुसूचित जाति जनसंख्या 25 प्रतिशत से अधिक है। बैठक में जांजगीर-चांपा जिला पंचायत अध्यक्ष सत्यलता आनंद मिरी, बिलासपुर से राजेश सूर्यवंशी, गरियाबंद से गौरीशंकर कश्यप, अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद एवं बसव राजू, पुलिस महानिदेशक अरुणदेव गौतम, विभागीय सचिव शहला निगार, रोहित यादव, कमलप्रीत सिंह, रीना बाबा साहेब कंगाले, आर. प्रसन्ना, शम्मी आबिदी सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सूचना-प्रसार में छत्तीसगढ़ बना रोल मॉडल, छत्तीसगढ़ संवाद व जनसंपर्क विभाग से प्रभावित हुए महाराष्ट्र के अधिकारी

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। महाराष्ट्र सरकार के जनसंपर्क एवं सूचना विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का एक अध्ययन दल 5 से 7 अगस्त 2025 तक तीन दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ में प्रवास पर रहा। इस दौरे का उद्देश्य छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सूचना, जनसंपर्क और शासकीय योजनाओं के प्रचार-प्रसार के क्षेत्र में किए जा रहे नवीनतम नवाचारों और प्रभावी कार्यप्रणालियों का प्रत्यक्ष अवलोकन एवं अध्ययन करना था।

अध्ययन दल में महाराष्ट्र शासन की उप सचिव समृद्धि अंगोलकर, निदेशक किशोर गंगरडे सहित कुल छह वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। दल ने छत्तीसगढ़ शासन के जनसंपर्क विभाग एवं उसकी सहायक संस्था छत्तीसगढ़ संवाद की संपूर्ण कार्यप्रणाली का अध्ययन किया। भ्रमण के दौरान अधिकारियों ने ई-न्यूज़ क्लिपिंग, ई-आरओ सिस्टम, ई-पब्लिकेशन, पत्रकार अधिमान्यता प्रणाली तथा पत्रकारों के कल्याण हेतु संचालित योजनाओं का गहन अध्ययन किया। इसके साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ संवाद की संगठनात्मक संरचना, संचालन तंत्र तथा तकनीकी नवाचारों के विभिन्न पहलुओं की विस्तृत जानकारी भी प्राप्त की।

इस अवसर पर अध्ययन दल ने जनसंपर्क विभाग के आयुक्त डॉ. रवि मित्तल से सौजन्य मुलाकात की। जनसंपर्क आयुक्त डॉ. मित्तल ने कहा कि छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग का यह सतत प्रयास रहा है कि शासकीय योजनाओं और जनहितकारी नीतियों की जानकारी आम जनता तक त्वरित, पारदर्शी और प्रभावशाली ढंग से पहुँचे। सूचना के क्षेत्र में तकनीक और मानवीय दृष्टिकोण के संतुलित समावेशन ने हमारी कार्यप्रणाली को विशिष्ट बनाया है। यह हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि अन्य राज्य भी हमारे नवाचारों में रुचि ले रहे हैं। यह अनुभव-साझाकरण एक सकारात्मक और रचनात्मक दिशा में उठाया गया कदम है।

अध्ययन दल ने इंद्रावती भवन स्थित जनसंपर्क संचालनालय एवं छत्तीसगढ़ संवाद कार्यालय का भ्रमण कर विभिन्न शाखाओं के संचालन का प्रत्यक्ष अवलोकन किया और विभाग की प्रमुख गतिविधियों को निकट से जाना। अपर संचालक जे.एल. दरियो, उमेश मिश्रा एवं संजीव तिवारी ने अध्ययन दल को विभाग की प्रमुख गतिविधियों, कार्यप्रणाली और तकनीकी अनुप्रयोगों की जानकारी विस्तार से प्रदान की।महाराष्ट्र से आए अध्ययन दल के सदस्यों ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सूचना एवं जनसंपर्क के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों की सराहना करते हुए उन्हें अपने राज्य में भी लागू करने की संभावनाओं में गहरी रुचि जताई। इस अवसर पर जनसंपर्क विभाग और छत्तीसगढ़ संवाद के विभिन्न अधिकारी उपस्थित थे।

महतारी वंदन योजनाः प्रतिमाह एक हजार रुपए से बच्चों के भविष्य की नींव रख रही पूर्णिमा

निःशुल्क राशन सहित कई योजनाओं का ले रही लाभ

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। शासन द्वारा आम नागरिकों के लिए कई जनहितैषी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, इनमें राशन, पेंशन, महतारी वंदन सहित विभिन्न विभागों के कई योजनाएं शामिल हैं। इन योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने मुंगेली कलेक्टर कुन्दन कुमार के निर्देशानुसार संबंधित विभागों द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है।

वहीं पात्र व्यक्तियों को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इनमें से एक काली माई वार्ड मुंगेली की श्रीमती पूर्णिमा बंजारा हैं, जो महतारी वंदन योजनांतर्गत प्रतिमाह मिलने वाले एक हजार रूपए से अपने बच्चों के सुरिक्षत भविष्य की नींव रख रही है। इसके साथ ही वे शासन की खाद्य सुरक्षा योजनांतर्गत नि:शुल्क राशन का भी लाभ ले रही हैं। पूर्णिमा ने बताया कि शासन द्वारा महतारी वंदन योजना के अंतर्गत प्रतिमाह एक हजार रूपए उनके खाते में आ जाते है। इस राशि को वे खर्च न कर अपने बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए बैंक में आरडी खाता खुलवाकर जमा कर रही हैं। उन्होंने बताया कि उनके दो बच्चे हैं, दोनों निजी स्कूलों में पढ़ाई करते हैं। छोटा लड़का शासन की नि:शुल्क शिक्षा का अधिकार योजना के तहत निजी स्कूल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर रहा है। उन्होंने इन सभी जनहितैषी योजनाओं के संचालन के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय, उप मुख्यमंत्री अरूण साव सहित शासन-प्रशासन को धन्यवाद ज्ञापित किया है।

बिहान दीदियों ने सजाया तिरंगा पंडाल

खरीद सकते हैं राखियां, पूजा सामग्री और तिरंगा

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत बिलासपुर जिला पंचायत परिसर में 'बिहान' (राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन) की दीदियों द्वारा स्टॉल लगाकर तिरंगे के साथ ही विभिन्न उत्पादों की बिक्री की जा रही है।

6 अगस्त से शुरू इस तीन दिवसीय प्रदर्शनी-सह-विक्रय केंद्र का संचालन 8 अगस्त तक किया जाएगा। बिलासपुर जिला प्रशासन ने शहरवासियों से स्टॉल में आकर स्वसहायता समूहों द्वारा बनाई गई सामग्रियों की खरीदारी के साथ ही 'हर घर तिरंगा' अभियान में भागीदारी की अपील की है।

'बिहान' की महिलाओं द्वारा संचालित इस प्रदर्शनी-सह-विक्रय केंद्र में स्वसहायता समूहों दीदियों द्वारा बनाए गए तिरंगा, राखियां, तिरंगा जैकेट, अगरबत्ती, पूजन व सजावट की सामग्री, आचार, पापड़ और अन्य घरेलू सामग्रियां बिक्री के लिए उपलब्ध है।

पहले ही दिन 6 अगस्त को महिलाओं ने अच्छा कारोबार करते हुए लगभग 20 हजार रुपए का समान बेचा। महिलाएं इन स्टालों के माध्यम से 'हर घर तिरंगा' और 'हर घर स्वच्छता' का संदेश भी दे रही हैं।

फसल परिवर्तन के लिए हर गांव की अलग-अलग कार्ययोजना पर जोर

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। बिलासपुर राजस्व संभाग के आयुक्त सुनील जैन की अध्यक्षता में हुई संभाग स्तरीय जल उपयोगिता समिति की बैठक में सिंचाई जलाशयों में जलभराव और फसलों के ताजा हालात की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि गत वर्षों की तुलना में इस वर्ष पर्याप्त वर्षा होने से खेती-किसानी के काम सुचारू रूप से चल रहे हैं। किसानों की ओर से कहीं से भी जलाशयों से कृषि कार्य के लिए पानी छोड़ने की मांग नहीं आई है।

बिलासपुर संभागायुक्त कार्यालय में आयोजित बैठक में विधायक व्यास कश्यप और फूलसिंह राठिया, बिलासपुर के कलेक्टर संजय अग्रवाल और जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता

जी.डी. रामटेके सहित संभाग स्तरीय अधिकारी मौजूद थे। संभाग के अन्य जिलों के कलेक्टर एवं अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल हुए।

जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने बैठक में बताया कि बिलासपुर संभाग के सभी बड़े, मध्यम एवं लघु जलाशयों में निस्तार एवं सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध है। मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना में 74 प्रतिशत, खारंग जलाशय में 110 प्रतिशत, मनियारी जलाशय में 109 प्रतिशत, निर्माणाधीन अरपा भैंसाझार बैराज में 20 प्रतिशत और केलो परियोजना में 49 प्रतिशत जल भराव है। मध्यम परियोजना के अंतर्गत घोंघा जलाशय में 102 प्रतिशत, केदार जलाशय में 75 प्रतिशत, पुटका जलाशय में 60 प्रतिशत, किंकारी जलाशय में 96 प्रतिशत और खम्हार पाकुर जलाशय में 100 प्रतिशत जल भराव है। संभाग के अंतर्गत 621 लघु जलाशय हैं जिनमें औसत रूप से 82 प्रतिशत जल भरा हुआ है। बैठक में रबी सिंचाई वर्ष 2024-25 की उपलब्धियों एवं खरीफसिंचाई 2025-26 के लक्ष्य प्राप्ति की विस्तृत समीक्षा की गई। संभागायुक्त सुनील जैन ने बैठक में खाद-बीज की उपलब्धता एवं वितरण की भी समीक्षा की। उन्होंने स्थानीय स्तर पर किसानों के संगठनों (एफ्पीओ) के जरिए बीज उत्पादन कार्यक्रम लिए जाने पर जोर दिया। उन्होंने एफ्पीओ को बीज प्रक्रिया केन्द्र में बीज उत्पादन कार्यक्रम में शामिल करने की अनुमति के लिए राज्य शासन को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। श्री जैन ने डीएपी के विकल्प के रूप में अनुशंसित खाद के उपयोग के संबंध में जागरूकता एवं इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।

श्री जैन ने किसानों के लिए खाद की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने डबल लॉक केन्द्रों से जल्दी से जल्दी सोसाइटीज में खाद भेजने को कहा। उन्होंने कहा कि खेती-किसानी का यह चरम समय है। आपूर्ति में जरा भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने फसल परिवर्तन के लिए किसानों को प्रेरित करने को कहा। उन्होंने इसके लिए हर गांव की अलग-अलग जरूरत को ध्यान में रखते हुए कार्ययोजना बनाने एवं जागरूकता के लिए जिला स्तरीय सम्मेलन आयोजित करने के निर्देश दिए।

नक्सल पीड़ित परिवारों और आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए बन रहे तीन हजार पीएम आवास

दुर्गम क्षेत्र और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद मात्र तीन महीनों में पूर्ण हुआ सोडी हुंगी और दशरी बाई का मकान

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दूरस्थ वनांचलों के हर परिवार को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने सरकार लगातार पहल कर रही है। राज्य में नक्सल पीड़ित परिवारों और आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास के लिए विशेष परियोजना के तहत करीब तीन हजार आवास बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र सरकार से विशेष आग्रह कर आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवारों के लिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता की शर्तों में नहीं आ पा रहे थे, उनके लिए विशेष परियोजना के तहत 15 हजार आवास स्वीकृत कराया है।

विशेष परियोजना के तहत राज्य में अब तक पात्र पाए गए पांच हजार परिवारों में से तीन हजार परिवारों के लिए आवास स्वीकृत कर

2111 परिवारों को आवास निर्माण के लिए पहली किस्त और 128 परिवारों को दूसरी किस्त भी जारी की जा चुकी है। सुदूर वनांचलों में रहने वाले इन परिवारों के आवास तेजी से बन रहे हैं। नक्सल हिंसा से प्रभावित सुकमा की सोडी हुंगी और कांकेर की दशरी बाई का विशेष परियोजना के अंतर्गत स्वीकृत पीएम आवास दुर्गम क्षेत्र और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद मात्र तीन महीनों में ही बनकर तैयार हो गया है। इस साल मार्च में स्वीकृति के बाद मई में इनके आवासों का निर्माण प्रारंभ हुआ था।

बस्तर में नक्सल हिंसा से प्रभावित और आत्मसमर्पित नक्सलियों के परिवारों में खुशियों ने फिर से दस्तक देना शुरू कर दिया है। विशेष परियोजना के तहत स्वीकृत उनके पक्के आवास तेजी से आकार ले रहे हैं। दूरस्थ और कठिन भौगोलिक क्षेत्र होने के बावजूद इन परिवारों के हौसले और शासन-प्रशासन की मदद से उनके सपनों के आशियाने मूर्त रूप ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की दिशा में यह विशेष परियोजना न केवल एक ठोस कदम है, बल्कि पीड़ित परिवारों के पुनर्वास की दिशा में मील का पत्थर भी है। श्रीमती दसरी बाई बताती हैं कि वनांचल और दूरस्थ क्षेत्र होने के कारण आवास के निर्माण में कई व्यावहारिक दिक्कतें आईं। विकासखंड मुख्यालय से बहुत दूर होने के कारण चारपहिया वाहनों के लिए कोई मार्ग नहीं है। इस कारण से निर्माण सामग्री लाने में बहुत कठिनाइयां आईं। बारिश होने पर दोपहिया वाहन से भी पहुंचना अत्यंत मुश्किल होता था, जिसके चलते राजमिस्त्री और श्रमिक समय पर पहुंचने से मना कर देते थे। अंदरूनी क्षेत्र होने से निर्माण सामग्रियों को लाना सामान्य क्षेत्र के मुकाबले महंगा पड़ता था।

श्रीमती दसरी बाई कहती हैं कि आवास का काम तेजी से पूरा करने में कांकेर जिला प्रशासन, ग्राम पंचायत और प्रधानमंत्री आवास योजना के अधिकारियों का बहुत सहयोग मिला। निर्माण सामग्रियां पहुंचाने तथा राजमिस्त्रियों और श्रमिकों की व्यवस्था में ग्राम पंचायत एवं आवास टोली ने बहुत सहायता की। वह कहती हैं कि नक्सल पीड़ितों और आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के पुनर्वास के लिए सरकार ने संवेदनशील और प्रभावी नीति बनाई है।

दुर्गम क्षेत्र और विपरीत हालातों के बीच भी तीन महीने में निर्माण पूरा

कांकेर जिला मुख्यालय से लगभग 200 किलोमीटर दूर कोयलीबेड़ा विकासखण्ड के उलिया ग्राम पंचायत में रहने वाली श्रीमती दसरी बाई नुरूटी के पति श्री दोगे नुरूटी की विधानसभा चुनाव के दौरान माओवादी घटना में मृत्यु हो गई थी। पीएम आवास योजना में नक्सल पीड़ित परिवारों के लिए विशेष परियोजना के तहत इस साल मार्च में उसका आवास स्वीकृत किया गया था। मई में उसके आवास का निर्माण शुरू हुआ था। अब मात्र तीन महीनों की अल्प अवधि में ही उसके आवास का निर्माण पूर्ण हो गया है। दसरी बाई के हौसले के कारण कठिन परिस्थितियों के बावजूद बहुत कम समय में आवास तैयार हुआ और उसके परिवार को पक्का मकान मिला।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक राजेश अग्रवाल द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि. छत्तीसगढ़ भवन, प्रेस काम्पलेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित कर, 204 आकाशगंगा सुपेला, भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.) से प्रकाशित। संपादक राजेश अग्रवाल shreekanchanpath2010@gmail.com, Mo - 9303289950